

कायदे, कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी न होना भारी पड़ रहा है, भाजपा पर संसद में

जो हश्र “प्रिवलेज मोशन” का हुआ, वह ही अंजाम राहुल को डिस्क्वालिफाई करने के हल्ले का होगा?

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भाजपा और निशिकांत दुबे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालिफाई करने की मांग करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। लेकिन यह धमकी इसलिए वापस ले ली गई, क्योंकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति अभी तक गठित ही नहीं हुई है। संभव है कि रिजिजू को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए एक तय प्रक्रिया और नियम होता है। पहले विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद मामला आचार समिति (एंथिक्स कमेटी) के पास जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसलिए प्लान बी के तौर पर निशिकांत दुबे को आगे किया गया।

- “प्रिवलेज मोशन” नहीं लाया गया, क्योंकि “प्रिवलेज कमेटी” का अभी तक गठन नहीं हुआ है। प्रिवलेज कमेटी प्रस्ताव का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देती है, जो “एंथिक्स कमेटी” के सामने प्रस्तुत होती है। “एंथिक्स कमेटी” की सिफारिश के बाद, निर्णय लिया जाता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ “प्रिवलेज मोशन” लाया जाए या नहीं। जब “प्रिवलेज कमेटी” का गठन ही नहीं हुआ अभी तक, तो “प्रिवलेज मोशन” की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ती।
- इसी प्रकार निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को “डिस्क्वालिफाई” करने की मुहिम शुरू की। पर, यह स्पष्ट नहीं था कि राहुल गांधी को किस “रूल” के अंतर्गत “डिस्क्वालिफाई” करने की मांग की जा रही है या किस प्रक्रिया के जरिए राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है।
- निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों की लाइन लगा दी, शून्यकाल में। पर, ये शिकायतें किसी भी “लैटर हैड” पर नहीं लिखी गई थीं तथा शिकायत पत्र पर किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं थे तथा यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह शिकायत पत्र किस के पास भेजा जाए।

उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन किस प्रस्ताव के तहत? किस नियम के तहत? किस प्रक्रिया के तहत? खुद सांसद को ही इसकी

जानकारी नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ शिकायतों की लंबी सूची लिखी और उसे शून्य काल में पढ़कर सुना दिया। जिस कागज पर शिकायत लिखी

गई, वह न तो कोई लेटरहेड था और न ही उस पर कोई हस्ताक्षर। यह शिकायत किसे संबोधित की गई थी? किसी को भी इसकी जानकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर काम शुरू होने से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान ने फिर से भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया

-श्रीरंज झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत-पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल कम होता नज़र नहीं आ रहा है और आने वाले समय में भी इसके शांत होने की संभावना कम दिखती है।

पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर इस्लामाबाद के खिलाफ “पानी रोकने की नीति” अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं, भारत का कहना है कि उसे अपने क्षेत्र के अंदर बुनियादी ढांचा बनाने और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बेहतर प्रबंधन का पूरा संप्रभु अधिकार है।

पाकिस्तान की ताजा आपत्ति चिनाब नदी पर 5129 करोड़ रुपये की लागत वाली सावलकोट जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की खबरों के बाद सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की

- भारत सरकार ने कहा, उसे अपने क्षेत्र में नदियों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
- इधर पाकिस्तान ने कहा कि उसकी पानी की तीन चौथाई जरूरत चिनाब जैसी नदियों से पूरी होती है, और भारत द्वारा बाँध बनाने से उसका पानी रुक जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने चिनाब पर 5129 करोड़ रूपए की लागत से सावलकोट पन बिजली योजना शुरू की है।

इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंचों पर चुनौती देगा। पहलगाम हत्याकांड और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर में कई जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है और कहा है कि अपने बुनियादी ढांचे का प्रबंधन

करना उसका संप्रभु अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि देश के भीतर शुरू की गई किसी भी विकास परियोजना का फैसला हमारी अपनी समझ के आधार पर होता है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा सावलकोट बांध, सिंधु जल संधि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश चुनावों से गायब हैं महिला नेता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। बांग्लादेश के चुनावी परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। कभी शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं से पहचाने

- शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी सशक्त महिला नेताओं का नेतृत्व देख चुके बांग्लादेश के आम चुनावों में मात्र 4 प्रतिशत महिलाएं ही चुनाव मैदान में दिखीं।

जाने वाले देश में अब मतपत्रों पर महिलाएं लगभग नदारद हैं। देशभर में केवल 4 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं, जिनमें से कई केवल पुरुष नेताओं से जुड़ी प्रतीकात्मक उम्मीदवार मानी जा रही हैं।

जहां कुछ इस्लामी दलों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” का नाम बदलने का नोटिस दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” के निर्माताओं को इसके कथित जातिसूचक शीर्षक को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि “फिल्म का नया नाम बताइए, नहीं तो रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फिल्म का नाम ब्राह्मण भावनाओं को आहत करता है। कोर्ट ने कहा, इसे बदलें, वरना रिलीज की अनुमति नहीं मिलेगी।

“घूसखोर पंडित” नैटफिलक्स पर रिलीज की घोषणा के बाद विवादों में घिर गई है। आरोप है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। अंग्रेजी में अनुवाद करने पर इस शीर्षक का मतलब एक भ्रष्ट ब्राह्मण होता है।

फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिंसा व हत्याओं के वातावरण में बांग्लादेश में चुनाव सम्पन्न

पिछले चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में गुरुवार को संसदीय चुनाव हुए, जो देशभर में गंभीर हिंसा और मतदान प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता के कारण प्रभावित रहे। यह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध प्रदर्शनों के बीच, भारत आ जाने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव है। मतपेटियों और मतदानकर्मियों को कड़ी सशस्त्र सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। हालांकि, मतदान के दौरान कई गड़बड़ियों की खबरें सामने आईं। इसके अलावा, मतदान में आम लोगों की भागीदारी का स्तर भी कम रहा, जो मुश्किल से आधे से थोड़ा अधिक ही पहुंच पाया।

भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हसीना ने चुनाव को फर्जी और एक ढोंग बताया। उन्होंने इसे रद्द करने की मांग की, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई और चुनाव लड़ने

- अब शेख हसीना की पार्टी चुनाव क्षेत्र में नहीं है, अतः बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी आमने-सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं।
- भारत के लिए एक तरफ खड़ा और दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि दोनों ही भारत विरोधी पार्टियां हैं, तथा बांग्लादेश से हिंदुओं को बाहर निकालकर फैंकना चाहती हैं। अजीबोगरीब बात है, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जब हिंदू विरोधी हिंसा व वारदातें कम होती थीं। ये घटनाएं अब कई गुना बढ़ गई हैं।

- बहरहाल, बांग्लादेश में वर्तमान गरीबी व कानून व्यवस्था भारत के लिए भारी संकट पैदा कर रही है, क्योंकि इस निर्धनता व बेरोज़गारी के कारण भारत के लिए पलायन करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है और भारत के लिए संकट व सुरक्षा का मुद्दा और गंभीर बनाता जा रहा है।

से भी रोक दिया गया।

इसके बजाय, विभिन्न स्तरों की

कट्टरपंथी सोच वाले राजनीतिक दलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा

लोकसभा सचिवालय ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर जोर-शोर से शुरू हुए राजनीतिक टकराव को हवा निकलती लग रही है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है।

इस घटनाक्रम ने राजधानी में तीव्र राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है, विशेषकर ऐसी खबरों के बाद, कि स्पीकर कार्यालय ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से स्वयं को अलग कर लिया है।

विवाद की शुरुआत लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के तीखे भाषण के बाद हुई। अपने भाषण में, जिसमें आर्थिक आलोचना के साथ

- विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाए जाने पर यह चर्चा भी है कि स्पीकर के कार्यालय ने ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू करने से खुद का अलग कर लिया है।
- गुरुवार सुबह भी संसद का माहौल उस समय काफी उग्र हो गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग कर दी।
- लेकिन शाम तक माहौल ठंडा पड़ चुका था, जब यह पता लगा कि न तो विशेषाधिकार प्रस्ताव का औपचारिक आवेदन आया है, न ही राहुल को “डिस्क्वालिफाई” करने का प्रस्ताव आया है।
- राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सत्ता पक्ष का पीछे हटना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम है। भले ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में हावी है, पर, संसद में उसके पास प्रचंड बहुमत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को डिस्क्वालिफाई करना न केवल उन्हें हीरो बना सकता है, बल्कि सहयोगी दलों को भी नाराज़ कर सकता है।

कड़ा राजनीतिक हमला भी शामिल था, गांधी ने कथित तौर पर तथाकथित “एस्पर्टोन फाइल्स” और उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का उल्लेख किया। सत्तापक्ष के सदस्यों के अनुसार, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की सीमा को स्पर्श कर रहा था। इसके तुरंत बाद, उनके भाषण के महत्वपूर्ण हिस्सों को संसदीय अभिलेखों से हटा दिया गया, और यह कदम स्वयं एक राजनीतिक विवाद का कारण बन गया।

गुरुवार सुबह राजनीतिक माहौल तब और गरमा गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने आक्रामक तवरों के लिए जाने जाते हैं, को कथित तौर पर गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपे जाने की खबरें आईं। सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों का तर्क (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेअसर रहा भारत बंद

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। गुरुवार को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के एक दिवसीय आान का सामान्य जनजीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा।

कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। राहुल गांधी और

- भारत बंद से अधिकांशतः जनजीवन सामान्य रहा, लेकिन तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में मिलाजुला असर दिखा।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यापार समझौते और श्रम कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि देश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘दूषित फल-सब्जियों की जांच के लिए 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं?’

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि हर जिले में फूड सेफ्टी लैब हो, ताकि लोगों को दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़े

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट व दूषित पानी में उगाई गई फल-सब्जियों से आमजन को होने वाली गंभीर बीमारियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं? राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश के हर जिले में एक प्रयोगशाला हो और वहां पर्याप्त प्रशिक्षित अधिकारी हों, जो नहरों व सिंचाई के अन्य स्ट्रोलों की जांच करके यह सुनिश्चित करें कि गंदे पानी व दवाइयों अथवा रसायनों के उपयोग से फल-सब्जियों की पैदावार नहीं की जाए। हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया है। अदालत ने अलग-

अलग डेयरियों में दूध के सैंपल फेल होने के प्रकरण को भी गंभीरता से लेते हुए आरसीडीएफ को पक्षकार बनाने हुए जवाब तलब किया है कि दूध एकत्र करने के बाद प्लांट में पैकिंग तक, वह जांच की किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ के समक्ष खाद्य पदार्थों में मिलावट तथा प्रदेश में फैल रहे कुपोषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें पूर्व महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी व उनके सहायक अधिवक्ता दर्श पारीक ने अदालत को बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर फल-सब्जियों को उगाने में फैक्ट्रियों तथा सीवरेज व गंदे नालों के दूषित पानी का उपयोग किया जाता है। न्यायमित्र सिंघवी ने कहा कि जयपुर के लोग चौमूं की सब्जियां पसंद करते हैं,

- अदालत ने आदेश दिए कि जिन नदी-नालों का पानी सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, वहां एस.टी.पी. और आरओ प्लांट लगाया जाए।
- हाईकोर्ट ने प्रदेश में कई डेयरी ब्रॉंड्स के दूध सैंपल फेल होने पर चिंता जताते हुए आरसीडीएफ से मिलावट रोकने तथा जांच की प्रक्रिया के बारे में पूछा।

लेकिन सांगानेर की नहीं, क्योंकि सांगानेर की जमीन में फैक्ट्रियों का दूषित पानी जा रहा है और यहां पैदा होने वाली सब्जियां इससे दूषित हो गई हैं। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि कुछ समय पहले द्रव्यवती नदी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) बंद हो गए थे और उसी गंदे पानी से फल-सब्जियां उगाई जा रही हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए न तो उपयुक्त

टैस्टिंग लैब हैं, यानी 4 जिलों पर केवल एक लैब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपयुक्त अधिकारी भी नहीं हैं, जो नालों के पानी की जांच के लिए प्रशिक्षित हों। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि टैस्टिंग लैब में अधिकारी नियुक्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अदालती आदेशों के कारण लंबित थी, परंतु राज्य सरकार ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। सुनवाई के दौरान यह दृश्य भी सामने आया कि नालों के पानी को ट्रीट करने के लिए एस.टी.पी. के साथ-साथ आरओ प्लांट भी लगाया जाए, परंतु प्रदेश के किसी भी जिले में एसटीपी के साथ आर.ओ. नहीं लगाया गया है। खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता से कहा कि 11 प्रयोगशालाओं से प्रदेश के सभी जिलों में कैसे काम चलेगा। आप यह अपेक्षा

करते हैं कि एक जिले का आदमी जांच के लिए दूसरे जिले में जाएगा। राज्य सरकार को देखना चाहिए कि हर जिले में प्रयोगशाला हो, वह लोगों के नजदीक हो, ताकि उसका उपयोग हो सके। इस पर एजी ने कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय है। अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि जिन नालों का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ-साथ आरओ प्लांट लगाया हुआ हो।

सोशल मीडिया पर मंदर डेयरी, अमूल और कंटी डिल्टाइट जैसे ब्रांड्स के दूध पैकेट्स के सैंपल जांच में फेल होने की जो खबरें चल रही हैं, वह मुद्दा भी सुनवाई के दौरान सामने आया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सीबीएसई ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि नए फॉर्मेट को समझने के लिए सीबीएसई की वैबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान व सामाजिक ज्ञान के नमूना प्रश्न पत्र को हल करें।

एजुकेशन (सीबीएसई) की शैक्षणिक वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नमूना प्रश्नपत्रों का अध्ययन करें। सीबीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

दस पिल्लरों के मजबूत आधार से लिखी जा रही 2047 के राजस्थान की इबारत

वैसे तो यह परंपरा रही है कि किसी भी सरकार का बजट हो और कितना ही विजनरी बजट हो पर सत्ता पक्ष उसके गुणगाण में लगता है तो विपक्ष कमियाँ ही कमियाँ देखने में जुट जाता है। इसलिए विल्टमेंप्री दिया कुमारी के 2 घंटे 54 मिनट के 143 पेज के बजट को लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना से अलग हटकर देखना ही सही मायने में उसके साथ न्याय हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के तीसरे बजट में खास बात यह है कि यह बजट दूरगामी सोच यानी कि 2047 की राजस्थान की इबारत लिखने का बढ़ता कदम है। इस बजट की विजनरी बजट इस मायने में कहा जा सकता है कि पहली बार किसी बजट को समग्रता से रखा गया है। भजनलाल सरकार ने बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से दस पिल्लरों का ठोस आधार दिया है। इसे यों भी समझा जा सकता है कि प्रदेश के विकास के दस पिल्लरों से 2047 के राजस्थान का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। पिल्लर्स भी इस तरह से तैयार किये गये हैं जिससे किसी तरह के संदेह की गुंजाइस नहीं रह जाती है। आधारभूत संरचना से लेकर 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी का रोडमैप इस बजट में देखा जा सकता है।

राजस्थान की सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट को 10 पिल्लरों का आधार दिया है। वैसे तो सभी दस पिल्लर्स अपने आपमें अपना महत्व रखते हैं पर जिस तरह से इन पिल्लरों को प्राथमिकता दी गई है उससे यह साफ हो गया है कि प्रदेश के विकास का सशक्त आधार तय करने पर जोर दिया गया है। बजट में पहला पिल्लर इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार का है तो अन्य पिल्लरों में क्रमशः नागरिक सुविधाओं में गुणात्मक जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन सशक्तिकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन-डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास-किसान कल्याण, हरित विकास-पर्यावरण सततता और आखिरी व 10 वां पिल्लर 2047 का राजस्थान का है। देखा जाएं तो यह सभी दसों पिल्लर राजस्थान और राजस्थानवासियों के समग्र विकास और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से गति देने वाले होने के साथ ही विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान, निरोगी राजस्थान, समृद्ध किसान-और खेती, औद्योगिक विकास, रोजगार और स्वरोजगार के विपुल अवसर, खनन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के बजट में अरावली संरक्षण के प्रति दर्द भी है तो संरक्षण के प्रति गंभीरता भी स्पष्टता दिखाई देती है।

देखा जाएं तो यह सभी दसों पिल्लर राजस्थान और राजस्थानवासियों के समग्र विकास और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से गति देने वाले होने के साथ ही विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान, निरोगी राजस्थान, समृद्ध किसान-और खेती, औद्योगिक विकास, रोजगार और स्वरोजगार के विपुल अवसर, खनन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। खासबात यह है कि प्रदेश के बजट में अरावली संरक्षण के प्रति दर्द भी है तो संरक्षण के प्रति गंभीरता भी स्पष्टता दिखाई देती है।

आधारभूत सुविधाएं और बेहतर कानून व्यवस्था किसी भी देश या प्रदेश में निर्बाध उपलब्ध होती है तो विकास की राह अपने आप खुलने लगती है। देशी-विदेशी निवेश आने लगता है तो औद्योगिक विकास से रोजगार और आय के साधन विकसित होते हैं। सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और इससे इकोनोमी को बूस्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जब समग्र विकास की रूपरेखा बनती है तो फिर निवासियों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आता ही है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजनरी सोच को इस तरह से समझा जा सकता है कि सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर औद्योगिक निवेश के करार किये गये। उसके बाद लगातार मोनेटरिंग का परिणाम है कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग के प्रयासों में तेजी आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने की जो पहल प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन से की है और अब प्रतिवर्ष इसके आयोजन का निर्णय किया है इसके भी सकारात्मक प्रयास आने ही हैं। क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों ने अपने उद्यम कौशल से देश-दुनिया में डंका बजा रखा है और अब सरकार की पहल से इसका लाभ प्रदेश को मिलना ही है। क्योंकि प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं और निवेश अनुरूप माहौल से प्रेरित होकर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आयेगी ही और इसका एक बड़ा कारण सरकार का प्रोएक्टिव रोल व दूसरा सरकार द्वारा प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने की भावनात्मक पहल है।

सवाल यह नहीं है कि किस क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया गया है या किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई है अपितु यह है कि समग्र रूप से दसों पिल्लर अपने-अपने क्षेत्रों में परफरमेंस दिखाते हैं तो 2047 की सशक्त इमारत तैयार होने से कोई नहीं रोक सकता। राज्य के बजट को इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है।

–अतिथि सम्पादक, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ लेखक)



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शुक्रवार 13 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र सायं 4:16 तक, वज्र योग रात्रि 3:23 तक, बालव करण दिन 2:26 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह कुमार योग सूर्योदय से दिन 2:26 तक है। राजयोग सायं 4:13 से सूर्योदय तक है। आज विजया एकादशी व्रत, संक्रांति पुण्य काल पूर्वान्ह में है।

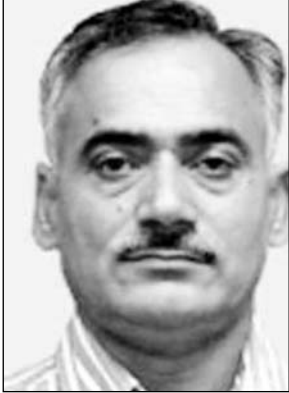
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:18 तक, शुभ 12:41 से 2:04 तक, चर 4:50 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:09, सूर्यास्त 6:13

 मेष नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 सिंह व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को उचित सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 धनु व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 वृष चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।	 कन्या घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 मकर घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनलल कार्यों में खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।
 मिथुन परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।	 तुला व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 कुंभ आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृद्धि होगी। संभावित खोस से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 कर्क व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिलेगी। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।	 वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 मीन व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्राप्ति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

राजस्थान बजट 2026-27 : सुदृढ़ कानून व्यवस्था से समृद्धि

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट सुरक्षा और समृद्धि के संतुलित समन्वय का दस्तावेज है



ओ. पी. गल्होत्रा

राजस्थान का बजट 2026-27 विकास की रूपरेखा होने के साथ ही सुरक्षित और विश्वासपूर्ण समाज के निर्माण का भी स्पष्ट संकल्प है। किसी भी राज्य की प्रगति का वास्तविक आधार उसकी कानून-व्यवस्था होती है। यदि नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, निवेशक निश्चित होकर पूंजी लाएँ, महिलाएँ और बच्चे भयमुक्त वातावरण में जीवन जी सकें, तभी विकास के सभी आंकड़े सार्थक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट सुरक्षा और समृद्धि के संतुलित समन्वय का दस्तावेज है। कुल 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये के आकार वाला यह बजट न केवल आर्थिक विस्तार को दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र

के सुदृढ़ीकरण की स्पष्ट दिशा भी देता है। बजट में किए गए प्रावधान प्रदेश में कानून-व्यवस्था को आधुनिक, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाने की व्यापक योजना प्रस्तुत करते हैं। बजट में पुलिस बल की संरचनात्मक मजबूती पर जोर दिया गया है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती और प्रशिक्षण व्यवस्था के आधुनिकीकरण का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से पुलिस बल पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए यह आवश्यक था कि बल की संख्या और क्षमता दोनों में वृद्धि हो। नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति से थानों में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा और गश्त व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। इससे न केवल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।यह पहल दर्शाती है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों के लिए वर्तमान में तैयारी कर रही है।

महिला सुरक्षा इस बजट की प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। प्रत्येक जिले में महिला सहायता डेस्क और विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ की स्थापना से पीड़ित महिलाओं को त्वरित और संवेदनशील सहायता मिलेगी। महिला अपराधों की जांच के लिए समयबद्ध प्रणाली और फास्ट ट्रैक दृष्टिकोण से न्याय की प्रक्रिया में गति आएगी। यह संदेश भी जाएगा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा के प्रश्न पर किसी प्रकार की हिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है।

पुलिस थानों के आधुनिकीकरण और डिजिटल केस मैनेजमेंट प्रणाली का विस्तार कानून-व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सीसीटीवीएनएस के उच्चम और डेटा इंटीग्रेशन से अपराधियों का ट्रैक रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध होगा, जिससे अपराधनियंत्रण की प्रक्रिया अधिक सटीक और त्वरित बनेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्ट सर्बिलॉस और सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिससे अपराध की संभावनाएँ स्वतः कम होंगी। समुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहन देने का निर्णय भी उल्लेखनीय है। कानून-व्यवस्था केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम होती है। नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत कर विश्वास का वातावरण बनाया जा सकता है। समुदायिक सहभागिता से स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान शीघ्र

होगा और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगेगा।

पुलिस कमियों के आवास, कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों के लिए विशेष संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। निरंतर दबाव में कार्य करने वाले पुलिस बल के मनोबल को बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना। जब बल संतुष्ट और प्रेरित होगा, तो उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इन सभी पहलों का परिणाम प्रदेश की समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति में स्पष्ट सुधार के रूप में सामने आया है। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और महिला अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई से अपराधियों में भय और नागरिकों में विश्वास का वातावरण बना है। निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध होने से औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विकास और सुरक्षा परस्पर पूरक हैं। जब राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 21 लाख 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुँचने का अनुमान हो, प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड निवेश हो, तो यह सब तभी सार्थक है जब समाज सुरक्षित हो। 53 हजार 978 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, शिक्षा के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़े

निवेश भी अंततः उसी सामाजिक स्थिरता पर निर्भर करते हैं, जिसकी नींव मजबूत कानून-व्यवस्था से पड़ती है।

कृषि, जल प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएँ सामाजिक असमानताओं को कम करती हैं और इससे अपराध के सामाजिक कारणों में कमी आती है। युवाओं को रोजगार के अवसर, पारदर्शी भर्ती प्रणाली और कौशल विकास कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। इस प्रकार यह बजट अपराध नियंत्रण को केवल दंडात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि संरचनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखता है। समग्र रूप से राजस्थान बजट 2026-27 यह स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार विकास को सुरक्षा से अलग नहीं मानती। आधुनिक पुलिसिंग, तकनीकी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, सामुदायिक सहभागिता और पुलिस कल्याण आदि सभी आयामों के माध्यम से प्रदेश में एक सुरक्षित, स्थिर और निवेश-अनुकूल वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया है।

इन घोषणाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन से राजस्थान न केवल आर्थिक प्रगति के मानकों पर, बल्कि कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी देश के अटाणी राज्यों में स्थान प्राप्त करेगा।

–ओ. पी. गल्होत्रा, महानिदेशक पुलिस (सेनि.)

समृद्ध राजस्थान की ओर निर्णायक कदम है प्रदेश का बजट



सीए सुनील भागंव

राजस्थान का बजट 2026-27 आय-व्यय का औपचारिक दस्तावेज होने के साथ ही राज्य की विकास-दृष्टि का सुसंगठित घोषणापत्र है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों के बजाय दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से समृद्ध प्रदेश के संकल्प को साकार करना चाहती है। लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपये के बजट आकार के साथ यह वित्तीय खाका विकास, सुशासन और सामाजिक संतुलन पर आधारित है। राजकोषीय प्रबंधन की दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने विकास व्यय में वृद्धि करते हुए भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। राजकोषीय घाटे (79 हजार करोड़ से अधिक) का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का

3.69 प्रतिशत रहना यह दर्शाता है कि सरकार ने जिम्मेदार वित्तीय नीति को प्राथमिकता दी है। अनुमानित 21.52 लाख करोड़ रुपये का सकल घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा, लॉजिस्टिक हब और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जैसे कदम उठाकर निवेश वातावरण को सुदृढ़ करने का संकेत दिया है। ~2024 के तहत मैनुफैक्चरिंग के साथ सेवा क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना औद्योगिक विस्तार की स्पष्ट दृष्टि को दर्शाता है। सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी संभव है जब निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को समानांतर गति दी जाए और बजट में इन तीनों आयामों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है।

समृद्ध प्रदेश की परिकल्पना युवाओं की सहभागिता के बिना अधूरी है। चार लाख भर्तियों के संकल्प को दिशा में एक लाख से अधिक नियुक्तियाँ और निजी क्षेत्र में दो लाख से अधिक रोजगार सृजन का उल्लेख राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन होना प्रशासनिक सक्रियता का संकेत है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करेगा। शिक्षा क्षेत्र में 400 विद्यालयों को – स्कूलों

में उन्नत करने हेतु 1,000 करोड़ रुपये का निवेश गुणवत्ता सुधार का ठोस प्रयास है। आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स और डिजिटल मेंटॉरिंग कार्यक्रम यह संकेत देते हैं कि सरकार शिक्षा को तकनीकी नवाचार से जोड़कर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना चाहती है। स्वास्थ्यक्षेत्र में आधुनिक विश्राम गुहों और जेके लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड के टॉवर के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए – कार्यक्रम और जिला स्तर पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना यह दर्शाती है कि सरकार स्वास्थ्य को केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं मानती। महिलाओं के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, ‘नंद घर’ मॉडल की आंगनबाड़ियों का विस्तार और लक्षपति दीदी योजना सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम हैं।

कृषि क्षेत्र में 11,300 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाएँ और 50 हजार सौर पंप संयंत्रों की योजना किसान हितैषी दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के व्याज मुक्त फसली ऋण का प्रावधान ठागीम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। राज मिशन के माध्यम से कृषि उत्पादों को वैश्विक पट्टाचन दिलाने का प्रयास कृषि के मूल्य संवर्धन और निर्यात से जोड़ता है।

‘हरियालो-राजस्थान’ के अंतर्गत से 90,445 करोड़ रुपये प्राप्ति। विकास घाटा और फिस्कल घाटा नियंत्रित स्तर पर हैं, जबकि कैपेक्स बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.6-1.9 प्रतिशत रहा, जो बेहतर प्रबंधन दर्शाता है। सरकार ने उद्यार को उत्पादक उपयोग में लगाया, जिससे भविष्य में व्याज बोझ कम होगा और विकास डिंकाउ बनेगा। यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए आशा की किरण है। 100 से अधिक योजनाएँ, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास को मॉडल पेश करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है। यह बजट राजस्थान को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाएगा और 2029 में राज्य की 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की तत्पर तेज कदम होगा।

लेखक राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है।

– डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

राजस्थान बजट 2026-27 : विकास की नई ऊंचाइयां और वित्तीय मजबूती का प्रमाण



डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

राजस्थान सरकार ने 2026-27 के लिए 6.11 लाख करोड़ रुपये (लगभग 6 लाख 10 हजार 956 करोड़) का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 42 प्रतिशत की अप्रत्याशित उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ने का प्रमाण मिलता है-41.39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब यह 21.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। प्रति

व्यक्ति आय 1.67 लाख से बढ़कर 2.02 लाख रुपये हो गई है, जो सरकार की कुशल नीतियों और संरचनात्मक सुधारों का परिणाम है। यह बजट न केवल आकार में बढ़ा है, बल्कि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जन-कल्याण पर केंद्रित है, जो विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।

बजट के आकार में यह वृद्धि राजस्थान की आर्थिक प्रगति का स्पष्ट संकेत है। पिछले वर्षों में जीएसडीपी की वृद्धि दर उच्च रही-2022-23 में 15.2, 2023-24 में 11.5 प्रतिशत, और 2024-25 में 17 प्रतिशत। 2025-26 के लिए जीएसडीपी 19.89 लाख करोड़ रुपये अनुमानित था, जो 16.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। अब 2026-27 में 21.52 लाख करोड़ रुपये का अनुमान राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान कर रहा है। यह वृद्धि कृषि, उद्योग, रियल्टीएल एनजी और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में विविधीकरण से संभव हुई है। कृषि जीएसडीपी का लगभग 27-30 प्रतिशत योगदान देती है,

जबकि उद्योग और सेवाएँ क्रमशः 27 प्रतिशत और 46 प्रतिशत के आसपास हैं। सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाया है।

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) इस बजट की सबसे मजबूत विशेषता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है-सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा पर फोकसा उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल जल पहुँचाने के लिए 6,800 करोड़ रुपये, बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क्स के लिए 3,000 करोड़ रुपये (विशेष रूप से 2,950 करोड़ का प्रावधान), और कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,427 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। 42,000 किमी नई सड़कों का निर्माण, 6,500 गांवों में जल कनेक्शन, सिनल-लैंड शहर, पीपम आवास योजना का विस्तार, और डूनेज-सड़क लाइट जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

केंद्र सरकार के 12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स से प्रेरित होकर राजस्थान भी इंफ्रास्ट्रक्चर-

लेड ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहा है। इससे रोजगार सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा, और राज्य की आर्थिक क्षमता मजबूत होगी।

अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि और कैपेक्स बढ़ोतरी से राज्य की समग्र प्रगति स्पष्ट है। राइजिंग राजस्थान माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स बाउंड पर हैं। यह डबल इंजन सरकार की सफलता है। कृषि क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये के व्याज-मुक्त ऋण, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 30,000 युवाओं को 10 लाख तक व्याज-मुक्त लोन, 400 इन्ोवेटिव स्कूल, होमगार्ड में 5,000 नए पद, और फ्री इलाज जैसी योजनाएँ आमजन की सेवा में सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती हैं। एमएफएमई, पर्यटन, और रियल्टीएल एनजी पर फोकस से राज्य को ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार का हब बनाया जा रहा है।

फिस्कल डिस्प्लिन बनाए रखते हुए यह विकास संभव हुआ है। राजस्व प्राप्तिवाँ मजबूत हुई हैं-केंद्रीय करों

से 90,445 करोड़ रुपये प्राप्ति। विकास घाटा और फिस्कल घाटा नियंत्रित स्तर पर हैं, जबकि कैपेक्स बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.6-1.9 प्रतिशत रहा, जो बेहतर प्रबंधन दर्शाता है। सरकार ने उद्यार को उत्पादक उपयोग में लगाया, जिससे भविष्य में व्याज बोझ कम होगा और विकास डिंकाउ बनेगा।

यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए आशा की किरण है। 100 से अधिक योजनाएँ, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास को मॉडल पेश करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है। यह बजट राजस्थान को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाएगा और 2029 में राज्य की 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की तत्पर तेज कदम होगा।

लेखक राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है।

– डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

सार-समाचार

कर्मचारी महासंघ ने बजट प्रति जलाई

जैसलमेर, (नि.सं.)। राजस्थान सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का विरोध हुआ। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले गुरवार को कर्मचारियों ने गांधी दर्शन के सामने बजट की प्रतियां जलाकर अपना गुस्सा जाहिर किया। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि प्रशासन धरातल से कट चुका है और केवल कागजी आंकड़ों और ब्रांडिंग के दम पर राज करने की कोशिश कर रहा है। महासंघ के जिला महामंत्री प्रकाश बिस्नोई खारा ने सरकार की कार्यशैली पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ टेंट, इवेंट, टारगेट और रैंकिंग के झूठे आंकड़ों में गुमराह है। मंत्री और अधिकारी ऐसी कमरों में बैठकर वीसी के जरिए राज चला रहे हैं, जबकि हकीकत में जमीनी स्तर पर कर्मचारी चुनौती हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने अपना अड्डियल रवैया नहीं बदला, तो आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि जैसलमेर जैसे सीमांत जिले में बजट की प्रतियां जलना इस बात का प्रमाण है कि सरकार संवादहीन हो चुकी है। जब सरकार अपने ही कर्मचारी संगठनों की बात नहीं सुन रही, तो आम जनता की समस्याओं का समाधान केवल कल्पना मात्र है। इस विरोध प्रदर्शन ने साफ कर दिया है कि 8 लाख 50 हजार नियमित कर्मचारियों और लाखों मानदेय कर्मियों की नाराजगी सरकार के लिए आने वाले समय में बड़ी चुनौती बन सकती है। कृषि पर्यवेक्षक अमनदीप और जिला अध्यक्ष भंवरलाल गर्ग के नेतृत्व में कर्मचारियों ने बजट की कमियों को बताते हुए कहा कि केंद्र के 2027 वाले फॉर्मूले का समर्थन कर केवल कमेट्री बनाने के नाम पर छलावा किया गया है।

पशुपालक परिवार को मिला संबल

बालोतरा, (नि.सं.)। निकटवर्ती गांव थान माता हिंगलाज, ग्राम पंचायत गुडा निवासी ममता रमेश कुमार का परिवार पशुपालन एवं कृषि पर आधारित है। परिवार की आजीविका मुख्य रूप से ऊंट पालन पर निर्भर रही है। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जानकारी पशु चिकित्सक, सिवाना द्वारा उन्हें दी गई। योजना के महत्व को समझते हुए उन्होंने अपने ऊंट का बीमा करवाया। कुछ समय बाद अचानक बीमारी के कारण ऊंट की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार पर आर्थिक संकट गहराने लगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने पशु चिकित्सालय सिवाना से संपर्क किया। आवश्यक दस्तावेज एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया पूरी करने के बाद राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत 40,0०0 रुपये की बीमा राशि सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित की गई। प्राप्त बीमा राशि से परिवार ने नया ऊंट खरीद लिया, जिससे उनकी आजीविका पुनः पटरी पर लौट आई। लाभार्थी ममता रमेश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार की इस सहायता से उनके परिवार को बड़ा आर्थिक संबल मिला है और संकट की घड़ी में सहारा मिला। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भजलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालकों, किसानों और ग्रामीण परिवारों के हित में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा जैसी योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही हैं और आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं। उन्होंने अन्य पशुपालक भाइयों-बहनों से अपील की कि वे भी राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अवश्य लें, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

जनगणना-2027 के लिए प्रशिक्षण शुरू

बालोतरा, (नि.सं.)। जनगणना-2027 की तैयारियों के तहत जिला स्तर पर नियमित सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण 12 से 14 फरवरी तक पंचायत समिति सभागार, पंचायत समिति बालोतरा में प्रारंभ हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ राज्य स्तरीय प्रशिक्षक हरि सिंह बिजारणियां एवं दिव्यांश चावला के स्वागत एवं अभिनंदन के साथ किया गया। इस अवसर पर उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, दीपाराम ने जनगणना-2027 के कार्य को निर्धारित समय सीमा में संपादित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रशिक्षण के कार्य-योजना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल मोड में आयोजित की जाएगी, जो पारदर्शिता एवं त्वरित डाटा संकलन की दिश में महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण के दौरान नियमित सहायकों को सीएमएमएस (ERUUS) पोर्टल, स्वागणना ऐप तथा जनगणना-2027 के अंतर्गत आमजन से पूछे जाने वाले प्रश्नों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही डिजिटल उपकरणों के माध्यम से डाटा संकलन, अपलोडिंग एवं सत्यापन की प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य नियमित सहायकों को तकनीकी रूप से दक्ष बनाना है, ताकि वे अपने-अपने चार्ज क्षेत्रों में जनगणना-2027 के कार्यों को प्रभावी, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर सकें। कार्यक्रम में संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

सहायक उपकरणों का वितरण 16 से

बालोतरा, (नि.सं.)। राज्य सरकार के आदेशानुसार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर के सहयोग से 16 से 18 फरवरी तक तीन दिवसीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर पांडे भवन रेलवे स्टेशन के सामने, बालोतरा में आयोजित होगा। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि शिविर के दौरान दिव्यांगजन एवं विशेष योग्यजन को विभिन्न सहायक उपकरण पूर्णतः नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र (कान की मशीन), कैलीपर, कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ, छडी, क्लोईड रिटक, वॉकर सहित बुजुर्गों एवं जरूरतमंदों के लिए अन्य सहायक उपकरण शामिल हैं। उन्होंने बताया कि शिविर का उद्देश्य दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाना एवं उनके जीवन को सुगम बनाना है। शिविर में विशेषज्ञों की टीम द्वारा लाभार्थियों का पंजीयन, परीक्षण एवं आवश्यकता अनुसार उपकरणों का वितरण किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने पात्र दिव्यांगजन एवं बुजुर्गों से अपील की है कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथियों में शिविर स्थल पर उपस्थित होकर इस योजना का लाभ उठाएं।

क्विज विजेताओं को पुरस्कार दिए

जालोर, (कासं)। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एवं राज्य के मुख्य सचिव के निदेशानुसार जिला प्रशासन एवं एनआईसी जालोेर द्वारा सुरक्षित इन्टरनेट सप्ताह के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यशाला, शपथ, क्विज इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में सुरक्षित इन्टरनेट दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम की क्विज प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागी प्रवीण कुमार, रमेश कुमार, मनोज, आनन्द बी शिर्वा, रमेश नाथ व सरोज को अतिरिक्त जिला कलक्टर जालोर राजेश मेवाड़ा ने पारितोषिक वितरण कर सम्मानित किया तथा एनआईसी टीम द्वारा किये जा रहे सुरक्षित इन्टरनेट सम्बंधित कार्यक्रमों की सराहना की। इस अवसर पर जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी डीआईओ लादेश शर्मा एवं जयेश सुदेशा उपस्थित रहे।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का स्वागत

जालोर, (नि.सं.)। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वात प्रदेश प्रवक्ता जोगेंद्रसिंह सिलोर के जालोर पहुंचने पर जिला महामंत्री गुर्जेंद्र सिंह सिसोदिया,नगर अध्यक्ष रवि सोलंकी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। नवनियुक्त प्रदेश प्रवक्ता जोगेंद्रसिंह सिलोर ने सभी कार्यकर्ताओं को भाजपा की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। आगामी निकाय ओर पंचायत चुनाव की तैयारी के लगने को कहा। इस मौके पर भाजपा जिला प्रवक्ता दिनेश महावर, जिला मन की बात संयोजक सुरेश सोलंकी, भाजपा सोशल मीडिया सभाग सहसंयोजक चंचलकट सुन्देश,परमवीर सिंह भाटी,दशरथसिंह भाटी,नगर उपाध्यक्ष अचलसिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जिला स्तरीय जनसुनवाई अब 26 को

पाली, (नि.सं.)। पाली जिले में 19 एवं 20 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली जनगणना-2027 की प्रशिक्षण कार्यशाला के कारण 19 फरवरी 2026 (तृतीय गुरुवार) को प्रस्तावित जिला स्तरीय जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। अब यह जनसुनवाई 26 फरवरी 2026 (चतुर्थ गुरुवार) को प्रातः 11ः०0 बजे भा.नि.रा. गांधी सेवा केन्द्र, डीओआईटीसी, कलेक्ट्रेट परिसर, पाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित की जाएगी।

महादेव की बारात निकलेगी

जोधपुर, (कासं) । भगवान महादेव की शादी जोधपुर में 15 फरवरी को घूमघूम से कारंवाई जाएगी। कार्यक्रम को लेकर शिव बारात महोत्सव समिति सरदारपुरा प्रखंड की ओर से तैयारियों की जा रही है। विवाह महोत्सव समिति अध्यक्ष सरोज मासी ने बताया कि कार्यक्रम में सभी शहरवासी आमंत्रित हैं। सभी बड़-चढकर हिस्सा लें।

पाली में के.के. गुप्ता ने स्वच्छता बढ़ाने पर जोर दिया

पाली, (नि.सं.)। स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान सरकार के ब्रांड एंबेसडर के. के. गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को कलैक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता संबंधी बैठक आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने चर्चा कर जानकारी ली और इस बारे में आवश्यक निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वच्छता मिशन को धरातल पर उतारना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। विकसित राज्य और विकसित जिले के निर्माण के लिए स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना आवश्यक है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की महता देश-विदेश में स्थापित हो चुकी है और स्वच्छता केवल गंदगी से मुक्ति ही नहीं दिलाती, बल्कि अनेक बीमारियों से भी बचाती है। किसी भी शहर के प्रति पर्यटकों का पहला दृष्टिकोण उसकी स्वच्छता से ही बनता है।

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही स्वच्छता सर्वेक्षण का निरीक्षण प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर सभी निकाय अधिकारी एवं कर्मचारी संकल्प लें कि स्वच्छता से जुड़े कार्य पूर्ण जिम्मेदारी, समर्पण और समयबद्धता से पूरे किए जाएं। कार्यों में मुख्यमंत्री की जोरो टॉलरेंस नीति का पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डूंगरपुर जिले के स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी रहने का उदाहरण देते हुए बताया कि टीम वर्क, जनजागरूकता, गीले-सूखे कचरे का पृथक निस्तारण, नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और सतत मॉनिटरिंग से



स्वच्छ भारत मिशन राजस्थान सरकार के ब्रांड एंबेसडर के. के. गुप्ता की अध्यक्षता में पाली के कलैक्ट्रेट सभागार में स्वच्छता संबंधी बैठक आयोजित हुई।

बेहतर परिणाम प्राप्त हुए।

बैठक में स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया गया, जिनमें 365 दिन नियमित डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले-सूखे कचरे की अलग व्यवस्था, नाइट स्वीपिंग, सार्वजनिक शौचालयों का बेहतर रखरखाव, सड़कों व नालियों

की नियमित सफाई, रोड लाइट व्यवस्था, बाग-बगीचों की साफ-सफाई, तालाब-झीलों का जौणोंद्वारा, अतिक्रमण हटाना, जियो-टैग आधारित मॉनिटरिंग, जागरूकता होर्डिंग तथा शिकायत निवारण टोल सेवा शामिल हैं। उन्होंने डूंगरपुर जिले की स्वच्छता सर्वेक्षण में अग्रणी बनाने में सहयोग देने

वाले निकाय अधिकारियों नरपत सिंह, लोकेश एवं विकास का आभार व्यक्त किया। अतिरिक्त जिला कलैक्टर सीलिंग ओम प्रभा, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सीपा, नगर निगम आयुक्त नवीन भारद्वाज, यूआईटी के विकास लेधा समेत ईओ, ईएन, इंजीनियर आदि मौजूद रहे।

सॉर्टेड सीमन से पशुपालकों की तकदीर बदलेगी

बालोतरा, (नि.सं.)। ग्राम पंचायत स्तर पर पशुपालकों को आधुनिक पशुपालन तकनीकों से जोड़ने के उद्देश्य से कार्यक्रम में सेक्स सॉर्टेड सीमन योजना की जानकारी दी जा रही है।

पशुपालन विभाग के उप निदेशक डॉ. मदन गिरी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना, नस्ल सुधार करना तथा पशुपालकों की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। सामान्य कृत्रिम गर्भाधान की तुलना में सेक्स सॉर्टेड सीमन तकनीक से मादा बछ्ों के जन्म की संभावना अधिक रहती है, जिससे भविष्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता वाले पशुओं की संख्या बढ़ती है। इस योजना के माध्यम से उन्नत नस्ल के पशुओं का संवर्धन किया जा रहा है, जिससे पशुधन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ग्राम पंचायत स्तर पर जागरूकता शिविर, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं परामर्श सत्र आयोजित कर पशुपालकों को वैज्ञानिक पशुपालन के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी पशु चिकित्सा संस्थान या पशुपालन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।

पशुपालक दोलाराम ने बताया कि सेक्स सॉर्टेड सीमन के उपयोग से अधिकतर बछड़ी के जन्म की संभावना रहती है। पशुपालक के अनुसार इस तकनीक से केवल बछड़ी पैदा होगी।



जालोर में भैरूनाथजी के अखाड़े के महंत गंगानाथ महाराज की उपस्थिति में नाथ जी के भक्त धर्मनारायण माली को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

जालोर, (का.सं.)। भैरूनाथजी के अखाड़े के महंत गंगानाथ महाराज, चातुर्मास सेवा समिति जालोर समेत शहर के लोगों ने स्वर्गीय धर्मनारायण माली को लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस अवसर पर गंगाप्रसादी के आयोजन के दौरान महंत गंगानाथ महाराज ने कहा कि व्यक्ति की पहचान कर्म से होती है। व्यक्ति को आध्यात्मिकता के साथ कर्म पर विशेष

ध्यान देना चाहिए। बेहतर कर्म कर मानव हित में कार्य करने से ही जीवन सफल होता है। इस दौरान सोजत के महा मंडलेश्वर चेतन गिरी महाराज, ईश्वरनाथ महाराज, साईनाथ महाराज, गोपालनाथ, निर्भयनाथ, ब्रह्माकुमारी आश्रम से शिल्पा दीदी समेत कई संत महत्तमा उपस्थित हुए। लोगों ने शोकाकुल परिवार के प्रकाशनारायण माली, नरेश गहलोत और तरुण गहलोत से लोग पहुंचे।

टीकाकरण कार्यक्रम संपन्न



जालोर के मुस्लिम मुसाफिर खाना में हज यात्रा पर जाने वालों का टीकाकरण किया।

फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर, (कासं)। मारवाड़ हज वेलफेयर सोसायटी जोधपुर एवं मुस्लिम वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट जालोर के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को मुस्लिम मुसाफिरखाना जालोर में हज यात्रियों का टीकाकरण कार्यक्रम ट्रस्ट के उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन कुरैशी की सदारत में आयोजित किया गया। ट्रस्ट के सचिव हाजी खान मेहर ने अली पैयदा का इंतकाल होने पर उनके हक में दुआएं मगाफित कर उनके द्द्वारा किये गये कार्यों को याद किया। वही जिले से कुल 44 हज यात्री मक्का मदीना की मुकदह हज यात्रा के लिए जा रहे हैं।उनके लिए मुस्लिम मुसाफिरखाना में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर टीकाकरण एवं प्रशिक्षण

कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रस्ट की ओर से प्रशिक्षण देने आए मेहमानों का मेडिकल टीम एवं हज पर जाने वाले हज यात्रियों का ट्रस्ट की ओर से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मारवाड़ हज वेलफेयर सोसायटी जोधपुर के हाजी अब्दुल जब्बार,काजी इकरामुद्दीन, जाकिर हुसैन, अब्दुल कयूम लोधी ने हाजियों को हज यात्रा के दौरान पूरे किए जाने वाले अरकान के बारे में जानकारी दी और हज यात्रा के बारे में मुख्य मुख्य बातें बताईं। वही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने टीकाकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का निरीक्षण किया। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से डॉ. जोयव, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर शहजाद खान,नर्सिंग ऑफिसर मोहम्मद

हाशिर, इंटर एनएम फहरिन, डाटा ऑपरेटर शाहबाज खान ने हज यात्रियों का टीकाकरण कर उनके स्वास्थ्य की जांच की। वही राजस्थान स्टेट हज निरीक्षक मोहम्मद साबिर रहमानी ने सभी हज यात्रियों का टीकाकरण करवा कर उनको हज यात्रा की जानकारी दी। कार्यक्रम में 44 हज यात्रियों को पोलियो दवा एवं टीकाकरण किया गया। शिविर में सभी हज यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। ट्रस्ट के सचिव हाजी खान मेहर नेआभार व्यक्त किया एवं कार्यक्रम का संचालन किया।

इस अवसर पर मौलाना गुलाम अली, गुलाब खान,समाजसेवी आले अहमद, अब्दुल रऊफ, इलियास खान बाग्रा, नगीना बनो रंगेज, हुसैन खान, आदि मौजूद रहे।

चौकेलाव गार्डन में पुस्तक का विमोचन आज

जोधपुर, (का.सं.)। पूर्व महाराजा गज सिंह जी (द्वितीय) के जीवन, कार्य शैली, विरासत संरक्षण, कला, संस्कृति व पर्यटन को बढ़ावा देने पर आधारित लिखित पुस्तक “बापजी: महाराजा ऑफ जोधपुर मारवाड़: दी किंग हू वुड बी मेन” का शुक्रवार 13 फरवरी को मेहरानगढ़ दुर्ग के चौकेलाव गार्डन में दोपहर 12.30 बजे विमोचन होगा। यह पुस्तक प्रसिद्ध लेखक अमन नाथ व योगी वैद्य द्वारा लिखी गई है और मैपिन पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित हुई है।

इस पुस्तक में महाराजा हनवन्त सिंह की 26 जनवरी, 1952 में हवाई दुर्घटना में देहान्त के बाद विकट व संकटमय परिस्थितियों में पूर्व महाराजा

ग्रेनाइट एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्यों पर अगली सुनवाई तक रोक

जालोर,(नि.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट, जोधपुर में ग्रेनाइट एसोसिएशन जालोर के चुनाव को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर की एकलपीठ ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक कार्यकारिणी सदस्यों पर रोक लगाई।

ग्रेनाइट उद्यमियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एस.बी. सिविल रिट याचिका पेश की। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि ग्रेनाइट एसोसिएशन जालोर के चुनाव आयोग के समन्वयक द्वारा बिना अधिकार एवं बिना सुनवाई का अवसर दिए ग्रेनाइट एसोसिएशन के 113 सदस्यों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए। इसी कथित अवैध मतदाता सूची के आधार पर चुनाव संपन्न कराए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि एसोसिएशन के

उपविधियों के अनुसार अधिकतम पांच पदों पर ही चुनाव हो सकते थे, जबकि नौ पदों पर चुनाव कराए गए, जो नियमों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वर्ष 1984 में पंजीकृत उपविधियों में अब तक कोई संशोधन नहीं हुआ है।

न्यायालय ने मामले को विचारणीय मानते हुए प्रतिवादि्यों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। साथ ही स्थान आवेदन पर भी नोटिस जारी किया गया है।

अंतिम आदेश में न्यायालय ने अगली सुनवाई तक कार्यकारिणी सदस्यों को ग्रेनाइट एसोसिएशन जालोर के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में कार्य करने से रोक दिया है। वे न्यायालय की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार से कार्य नहीं कर सकेंगे।

पशु मेला ग्राउंड व व्यवस्थाओं का निरीक्षण

जालोर/सायला, (कासं)। मां काल्यायनी देवी राज्य स्तरीय पशु मेला सायला का आयोजन आगामी 15 से 19 फरवरी तक किया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर अंतिम चरण में कार्य जोरों पर चल रहा है।

गुरुवार को सायला का पूरा प्रशासनिक अमला पशु मेला ग्राउंड पहुंचा और व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान एसडीएम सूरजभान बिस्नोई, तहसीलदार लक्ष्मी चौधरी, ईओ सुशील राजपुरोहित, सब इंस्पेक्टर महिपालसिंह तथा डॉ. संजय माली ने मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेला संरक्षक एवं पूर्व सरपंच सुरेश राजपुरोहित ने मेले की संपूर्ण व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए बताया कि साफ-सफाई, पेयजल, विद्युत व्यवस्था, पशुओं के ठहराव, सुरक्षा प्रबंध एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की समुचित तैयारी की जा रही है, ताकि मेला सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।

इस अवसर पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगलसिंह सायला, उपाध्यक्ष बलवंताजी आसाणा, महासचिव एवं पूर्व प्रधान हडमतसिंह सोढा, कोषाध्यक्ष नरेंद्र सिंह ओटवाला, पशुधन प्रसारक रवीन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह सायला, बाबूलाल राजपुरोहित, मिट्ठूदास सायला, पोडव सिंह चोराऊ ओटवाला, मांघुसिंह जी सायला सहित मेला समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। प्रशासन एवं मेला समिति द्वारा आपसी समन्वय के साथ तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

वही राज्य के पशुपालन एवं गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत 15 फरवरी को जालोर जिले के दौर पर रहेंगे। प्राप्त कार्यक्रमानुसार राज्य के पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत 15 फरवरी को प्रातः 9.30 बजे से सुरमपुर से रवाना होकर प्रातः 1०.30 बजे सायला पहुंचेंगे जहाँ वे जिला पशु मेले के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लेंगे। तत्पश्चात् वे साण्डेराव प्रस्थान करेंगे।

भुवनेश्वर चौहान ने बाल विवाह मुक्ति वाहिनी रवाना की

बालोतरा, (नि.सं.)। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत बाल विवाह रोकने एवं आमजन में व्यापक जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से गुरुवार को जिला मुख्यालय से बाल विवाह मुक्ति वाहिनी को अतिरिक्त जिला कलेक्टर भुवनेश्वर सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलैक्टर चौहान ने कहा कि बालविवाह एक सामाजिक बुराई है, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसे समाप्त करने के लिए प्रशासन, विभागों एवं समाज के सभी वर्गों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जन जागरूकता ही इस कुप्रथा के उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है और यह अभियान उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र सिंह ने बताया कि यह सी दिवसीय जन जागरूकता अभियान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सृष्टि संगठन के

प्रदेश में मा. शि. बोर्ड की परीक्षायें शुरु

पहले दिन सैकेण्डरी की अंग्रेजी अनिवार्य तथा सीनियर सैकेण्डरी की मनोविज्ञान की परीक्षा हुई

अजमेर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की गुब्बारा से औपचारिक शुरुआत हो गई। पहले दिन सैकेण्डरी में अंग्रेजी अनिवार्य तथा सीनियर सैकेण्डरी में मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही, कई छात्रों ने प्रश्नपत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में हल्की घबराहट के साथ-साथ संतोष भी देखने को मिला। अधिकांश छात्राओं का कहना था कि प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुसार था और समय पर पूरा हो गया। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि प्राम्तर और रीडिंग सेक्शन के कुछ प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन थे, जिनमें सोचने में अधिक समय लगा।

इधर, बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ स्वयं सक्रिय नजर आए। उन्होंने बोर्ड परिसर में संचालित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और विभिन्न परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की



प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार को 10वीं व 12वीं की परीक्षा हुई।

समीक्षा की। बोर्ड सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न कराई जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नकल की शिकायत न आए। बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थी

पंजीकृत हैं। प्रदेशभर में 6194 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा और गिरगरी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं तथा संवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षाओं का पहला दिन सफल और शांतिपूर्ण रहा। अब आने वाले दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित

होंगी, जिनको लेकर विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं।

वहीं नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से गिरगरी की जा रही है। उड़नदस्तों और विशेष दलों की तैनाती की गई है। इस बार अभय कर्मांड सेंट्रर्स के माध्यम से भी जिलों

- 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर बाहर आए कई छात्रों ने प्रश्नपत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया

- बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ सक्रिय नजर आए

के परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बोर्ड परिसर में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ तथा सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित अधिकारियों ने विधिवत पूजा-अर्चना की और सीसीटीवी कक्ष व कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया।

उदयपुर : सिलाई कर रही महिला पर चाकू से हमला , हालत गंभीर

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले के कुराबड थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम सिलाई का काम कर रही एक महिला पर अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। महिला गंभीर घायल हो गई, जिसके बाद उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। खून ज्यादा बहने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।

हॉस्पिटल में भर्ती घायल महिला ने बताया कि हमले के दौरान वह चिल्लाती हुई दुकान से बाहर आई और लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन लोग तमाशे की तरह देखते रहे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। थानाधिकारी तेजु सिंह ने बताया कि कुराबड के ब्रह्मपुर में आसपास (35) पुत्री फैजाना शाह अपनी दुकान पर सिलाई कर रही थी। तभी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। पुलिस आसपास सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुटी है।

जाकारी अनुसार आरोपी अपने बहन के कपड़े सिलाई के बाद लेने की बात कह रहा था, लेकिन पीड़िता ने ऐसे कोई कपड़े होने से इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया।

- बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर तीन वार किए
- पुलिस आसपास सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुटी

फिर करीब 20 मिनट बाद वापस लौटा और सिलाई करती महिला पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर तीन वार किए। जिससे वह घायल हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कुराबड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना के स्पष्ट कारणों की तलाश में जुटी है। घायल महिला की मामी गुलनाज बानो के अनुसार आरोपी ने यासमीन पर तीन बार चाकू से वार किए। मौके पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हम घायल को हॉस्पिटल लाए तब भी पुलिस साथ नहीं थी।

महिला की चेन छीनने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थाना पुलिस ने महिला दुकानदार को चाकू दिखा उसके गले से सोने की चेन छीनने के मामले में पहाड़ा थाने के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 11 फरवरी को पीड़िता सुनिता पत्नी बन्नीलाल कलाल निवासी तीतरड़ी अम्बामाता घाटी सविना ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरी गायत्री किरणा स्टोर पर शाम को मुंह बांध कर दो लड़के आए तथा सिगरेट लेने के बहाने बातचीत करते हुए मेरी गर्दन पर झपट्टा मार कर सोने की चेन छीन कर भाग रहे थे। इसको देख चिल्लाने पर लोगों ने घेरा डाल कर पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश चाकू दिखा कर बाइक से उतर कर फरार हो गया। डिटेन्शुदा बाल अपचारी की सूचना मिलने पर सविना थानाधिकारी गजवीरसिंह मय टीम ने जोगी तालाब 200 फीट रोड़ के समीप झाड़ियों में छिपा भवर लाल पुत्र लक्ष्मण लाल मीणा निवासी सेररा फला बिचला पहाड़ा पुलिस को जांच की कर भागा जो गिरने पर चोटिल होने पर चिकित्सालय में उपचार कराया। भवरलाल पहाड़ा थाने का बदमाश होकर उसके खिलाफ कई अपराधीक प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था।

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउनहॉल बिल्डिंग रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दुरभाष सं 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.mcudalpur.org.com

क्रमांक:- एस्.को./ 2025/26 / 209 दिनांक:-10.02.26

ई-बोली आमन्त्रण सूचना संख्या-ई- 01/2025-26

नगर निगम उदयपुर द्वारा अल्पाहार, भोजन व पानी कैंपेर सलाई कार्य की दर संविदा हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की अनुमानित लागत ३०.०० लाख है। ऑनलाइन निविदा फार्म मिलने की प्रारंभ दिनांक 11.02.26 अंतिम दिनांक 23.02.26 तथा खुलने की दिनांक 24.02.26 रहेगी।

UBN No. UNP2526GLRC00150 आयुक्त नगर निगम, उदयपुर

राज.सं.वाद /सी / 25 / 19723

कार्यालय नगर पालिका हिण्डोली जिला - बून्दी (राज0)

क्रमांक :- न0पाशि0/निर्माण / 2025-26 / 3265 दिनांक :- 09.02.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 22 /2025-26

नगर पालिका हिण्डोली द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु नगर पालिका हिण्डोली में पंजीकृत कार्यों के अनुसार स्वाम स्वतः के संवेद्यक एवं अन्य विभागों में पंजीकृत A.A.A. श्रेणी के संवेद्यकों से डी लिक्वाका पद्धति/ई-निविदा पद्धति से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 10.02.2026 से तथा अपलोड करने की दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 23.02.2026 तक है। जिसकी कुल लागत ५4.50 लाख है। निविदा भेजें आदि सम्पूर्ण विवरण <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

NIB CODE :- DLB2526B1447

Sr.No.	UBN No.	Tender Cost in lakh
1	DLB2526WSRC33761	24.96
2	DLB2526WSRC33762	29.54

राज.सं.वाद /सी / 25 / 19697 प्रशासक अधिशासी अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद टोंक

क्रमांक :- न.प.टी.क./निर्माण / 2025-26 / 14290 दिनांक :- 09.02.2026

NOTICE INVITING TENDERS THROUGH NIT No 87 / 2025-26

Bids are invited from interested bidders from 10.02.2026 (10.00AM) to 23.02.2026 (6.00PM) as per following details. Other particulars of he bid may be visited on procurement portal (www.Sppp.Rajasthan.gov.in) of the state

NIB No. DLB2526B1403

NIT No.	Name of work	UBN No.
87/2025-26	आईडीएआरएमटी कॉलोनी मे सेक्टर नं. बी एवं सी के पार्क का सौन्दर्यकरण करने का कार्य (अनुमानित राशि 29.98 लाख)	DLB2526WSOB33593

Date & time of opening of tender 24.02.2026 at 3.00PM

अति0 जिला कलक्टर आयुक्त एवं प्राधिकारी / प्रशासक नगर परिषद, टोंक

राज.सं.वाद /सी / 25 / 19677 न0पटी0क

राजस्थान सरकार

वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

राजभवन रोड, सिविल लार्न्स, नयापुर, कोटा-324001 दूरभाष/फैक्स 0744-2322747 (ई मेल आई.डी. dcfl.kota.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक- एफ।1 स्टीर/असई/2025-26/890 दिनांक-01.02.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 48/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से MSME / SSI Unit / अधिकृत पंजीकृत निर्माताओं/ विक्रेताओं/सप्लायर्स से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरएफबीडीपी योजनान्तर्गत इस कार्यालय के अधीन विभिन्न रेजो लाइपुर, मण्डाना, मोडक, कनवास, सुल्तापुर, ईटावा एवं खालोली के क्षेत्राधिकारी अधीन राजकीय विद्यालयों हेतु विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था हेतु आयर्न टेबल कम बेंचस को क्रय करने के लिए द्वि-स्तरीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक दर अनुबंध पद्धती के आधार पर ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त निविदा को ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि 15.02.2026 को सायं 06.00 बजे तक है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार साईट्स परदेखा जा सकता है।

<https://sppp.rajasthan.gov.in> एवं www.eproc.raajasthan.gov.in

UBN NO. 1- FOR2526WSOB05315 (अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव) उप वन संरक्षक कोटा (राज.)

DIPRC/2717/2026

भारत-पाक बॉर्डर पर 10 करोड़ की हेरोइन मिली

बीकानेर, (निर्सं)। भारत-पाक बॉर्डर पर बीकानेर जिले के खाजुवाला क्षेत्र में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हेरोइन गिराई गई है। बॉर्डर से 2 किमी दूर मिला 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन जो खाजुवाला के कार्यवाहक एसएसएओ हरपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात बॉर्डर के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। आशंका की कि ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ गिराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रात करीब एक बजे तक 14 बीड़ी के पास बॉर्डर से करीब दो किलोमीटर दूर एक पीले रंग का पैकेट बरामद हुआ। जांच में उसमें करीब 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन होने की पुष्टि हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बरामद पैकेट में दो

- बीकानेर जिले के खाजुवाला क्षेत्र में ड्रोन से गिराई गई थी हेरोइन

छड़ें लगी हुई थी, जिन्हें संभवतः ड्रोन से जोड़कर गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जांच में साफ है कि तस्करों ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा पार से खप भेजी। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ थाना प्रभारी समरवीर को सौंपी है। आसपास के क्षेत्र में सर्वे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खाजुवाला क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 8 जनवरी को चक 40 केजेडी में भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई करीब ढाई करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई थी। उस समय 500 ग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी।

बेटी की शादी के एक दिन पहले मां की हादसे में मौत

देवर के साथ कार्ड बांटकर लौटते समय बाइक से गिर गई थी महिला

डूंगरपुर, (निर्सं)। सदर थाना क्षेत्र में पालवड़ा के पास देवर की बाइक के पीछे बैठी भाभी की नीचे गिरने से मौत हो गई। बेटी की शादी के एक दिन पहले ही मां की मौत से परिवार ने मातम पससर गया। देवर और भाभी दोनों ही शादी के कार्ड बांटने के बाद वापस घर लौट रहे थे।

सदर थाना पुलिस के अनुसार धर्मनारायण मीणा निवासी कलावत फला आमली डूंगरी थाना ऋषभदेव

उदयपुर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया कि उसकी बेटी की 13 फरवरी को शादी है। बुधवार को पत्नी काली देवी (50) और छोटा भाई कांतिलाल दोनों ही बाइक लेकर शादी के कार्ड बांटने डूंगरपुर के देवल गांव गए थे। दोनों ही निर्मंत्रण पत्र देकर वापस बाइक से जा रहे थे। पालवड़ा स्कूल के पहले ही महिला काली देवी अचानक बाइक से नीचे गिर गईं। महिला के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर

चोटें आईं। उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच के बाद काली देवी की मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद शादी के घर में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है।

सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला

बीकानेर, (निर्सं)। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र छतरगढ़ में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा दिखाई दिया है। पहले भी कई बार ऐसे ही गुब्बारे सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाईंस लिखा हुआ है। गुब्बारा मिलने की सूचना मिलते ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना कर दी।

छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुब्बारे की स्थिति, उस पर लिखे शब्दों और उसके आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब छतरगढ़ या बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के गुब्बारे मिले हों। इससे पहले भी कई बार बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए गुब्बारे बरामद हो चुके हैं। कई बार इन गुब्बारों पर अलग-अलग कंपनियों, संस्थानों या पाकिस्तान से जुड़े नाम भी लिखे मिले हैं। सीमा पार से ऐसे गुब्बारे अक्सर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने, क्षेत्र में भ्रम फैलाने या किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने की मंशा से भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं क्योंकि कई बार इन गुब्बारों के साथ संदिग्ध सामग्री, संदेश या तकनीकी उपकरण भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल गुब्बारे की जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसे सुरक्षा एजेंसियों व विशेषज्ञ टीम को सौंपा जाएगा।

बोरवेल खुदाई में निकली चांदी जैसी धातु लूटने पहुंचे लोग

- बोरवेल में पानी-मिट्टी के साथ निकले दुकड़े, 15 किलो पत्थर मजदूर और लोगों ने लूटा
- यह बोरवेल जलदाय विभाग की ओर से करवाया जा रहा है, फिलहाल काम को रोक दिया

अलवर, (निर्सं)। अलवर में बोरवेल करते समय चांदी जैसी धातु के टुकड़े निकले। यह सब देखकर सबसे पहले बोरवेल करने वाले मजदूर ही पत्थर लूटने लगे। इसके बाद आसपास के दुकानदार और लोग भी धातु के टुकड़े ले गए। मामला अरकापुरी इलाके में गुरुवार को करीब 1:30 बजे का है। यह बोरवेल जलदाय विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। फिलहाल काम को रोक दिया है।

बोरवेल कर रहे मजदूर शहरख खान ने बताया कि यहां से लोग करीब 10 से 15 किलो वजन के चांदीनुमा पत्थर ले गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि जमीन के नीचे से आए चमकीले पत्थरों में चांदी कितनी प्रतिशत है। बोरवेल करते समय करीब 800 फीट तक मशीन से खुदाई हुई तो पानी-मिट्टी के प्रेशर के साथ नीचे जमीन से चांदी जैसी धातु के पत्थर निकले।

मजदूर शहरख खान ने बताया कि यहां 800 फीट गहरा बोरवेल करना था। इसमें आखिरी में जमीन की 20 फीट खुदाई तक मशीन पहुंची, तब यह चमकीला पत्थर निकलने लगा। आम तौर पर बोरवेल के नीचे से अलग-अलग तरह के पत्थर आ जाते हैं, लेकिन यह कुछ अलग है। इसमें धातु हो सकती है। आखिरी में करीब 5 से 10 प्रतिशत ऐसा पत्थर आया है। मशीन पर काम

कर रहे मजदूर ही चांदी जैसे पत्थर लूटने लगे। उनको देख आसपास के दुकानदार भी आ गए। आसपास के काफी लोग पानी और मिट्टी के अंदर से दूँकर चमकीले पत्थर के टुकड़े लेकर गए हैं। मशीन पर काम करने वाले ऑपरेटर भरत प्रजापत ने बताया कि हम कुछ नहीं कह सकते कि यह सिल्वर है। अभी 800 फीट के आसपास खुदाई हुई है, उसके बाद यह पत्थर आया है।

चमकीले पत्थर इकट्ठा कर रहे युवक महेश चंद सैनी ने बताया कि ये कि चांदी या सोना हो सकता है। लोग करीब 15 किलो के आसपास पत्थर ले गए।

ट्रेन की चपेट से युवक की मौत

बयाना/भरतपुर, (निर्सं)। बयाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना रुदावल थाना क्षेत्र के ब्रह्मबाद रेलवे फाटक के पास की बताई जा रही है। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जानकारी ली।

जानकारी के अनुसार युवक रेलवे पटरी पार कर रहा था, तभी अचानक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही बंध बरोटा थाना इंचार्ज भरतलाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रुदावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा पुत्र भूदेव निवासी गांव ककलपुरा के रूप में हुई है। पुलिस ने परिजनों की सूचना दे दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है।

Office of the Medical Superintendent

RUHS Hospital, Jaipur

Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur-302033
Ph. 0141-2792253 Email: supdt.hms@ruhsraj.org
Date: 09/02/2026

No. RUHS/HMS/Manpower/2025-26/13922

अल्पकालीन ई निविदा सूचना

राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान चिकित्सालय में कार्य की प्रकृति के आधार पर अकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल मैन पावर सेवाओं के उद्योगन हेतु निर्धारित दर संविदा प्रपत्र अनुसार ई उद्योगन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत राशि रु. 600 लाख)

1.	Bid Download Start Date/Time	09/02/2026 from 05:00 PM onwards
2.	Bid Submission Start Date/Time	09/02/2026 from 05:00 PM onwards
3.	Bid Submission End Date/Time	06/03/2026 at 02:00 PM
4.	Technical Bid Opening Date/Time	07/03/2026 at 02:00 PM

* Details may be seen in the bidding document at <https://eproc.raajasthan.gov.in> or <https://sppp.raajasthan.gov.in>

UBN: CMS2526SLRC00115 Medical Superintendent
Raj.Samwadi/C/25/19737 RUHS Hospital, Jaipur

राजस्थान-सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन-2 गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक-F.32(B)(After Policy 2026-27)/ex/II/2026-06481-9018219/693 दिनांक-11.02.2026

कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2026-27 के लिये अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिये आवेदन (विकल्प प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाई जाने की सूचना)

इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञापित क्रमांक 665 दिनांक 28.01.2026 के कन्वर्न में राज्य के कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के लिए अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के लिए पात्र एवं इच्छुक अनुज्ञाधारी अपना नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) पत्र मय निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ दिनांक 16.02.2026 तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 16.02.2026 तक नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) प्राप्त नहीं होने पर अनुज्ञाधारी का नवीनीकरण कर्वाण को विकल्प समाप्त हो जावेगा। तथा दुकान/समूह (Cluster) का आवेदन ई-नीलामी/ई-निविदा द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण से संबंधित समस्त जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <https://iems.raajasthan.gov.in> का अवलोकन करें। अन्य सभी भर्त पूर्तानुसार यथावत रहेंगे।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

DIPRC/ /2026

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

PHED DIVISION KARauli

PHNO.-07464-250219 E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for various works under summer contingency are invited from interested bidders up to 24.02.2026 other particulars of the bid may be visited eproc.raajasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website. on the procurement portal

NIB CODE:-PHE2526A5986

S.N.	NIT NO.	UBN	S.N.	NIT NO.	UBN
1	142/2025-26	PHE2526WSOB12758	9	150/2025-26	PHE2526WSOB12771
2	143/2025-26	PHE2526WSOB12759	10	151/2025-26	PHE2526WSOB12773
3	144/2025-26	PHE2526WSOB12762	11	152/2025-26	PHE2526WSOB12774
4	145/2025-26	PHE2526WSOB12763	12	153/2025-26	PHE2526WSOB12776
5	146/2025-26	PHE2526WSOB12765	13	154/2025-26	PHE2526WSOB12777
6	147/2025-26	PHE2526WSOB12766	14	155/2025-26	PHE2526WSOB12779
7	148/2025-26	PHE2526WSOB12769	15	156/2025-26	PHE2526WSOB12780
8	149/2025-26	PHE2526WSOB12770	16	157/2025-26	PHE2526WSOB12781
01		Total work			16
02		Total Estimate Cost			63.29 Lac
03		Bid submission end date			24.02.2026 up to 06.00 PM
04		Bid opening date			25.02.2026 at 02.00 PM

(Vijay Kumar Meena)
Executive Engineer
PHED Division Karauli

DIPRC/C/2411/2026

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम.-प्रथम)
पुराना पॉवर हाउस, बनीपार्क, जयपुर टेलीफैक्स: 0141-2208098

निविदा सूचना

एल टी एक्स एल पी ई इंसुलेटेड एरियल बन्ड केबल, बेयर मेसेन्जर वायर के साथ (1Cx25+25 Sq.mm) निविदा संख्या- 5071) (UBN- VVN2526GLOB00979), 2 कोर एलटी पीसीसी आरएमड केबल (2Cx4 Sq.mm) (निविदा संख्या-5072) (UBN- VVN2526GLOB00980), ए सी एस आर डोंग कंवक्टर (निविदा संख्या-5073) (UBN- VVN2526GLOB00981), फंजीकेटेड स्टील आइटम (ब्लेन्डेड) 33 केवी कॉस आर्म्स मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केवी कॉस आर्म्स (65x65x6) मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केवी टॉप हैम्पर बिना क्लैम्प, एलटी कॉस ब्रेकेट 4" लम्बे एवं 2" लम्बे, (निविदा संख्या-5074) (UBN- VVN2526GLOB00983), 33 केवी जी आई पिन (निविदा संख्या-5075) (UBN- VVN2526GLOB00982), 11 केवी पिन इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5076) (UBN- VVN2526GLOB00984), 11 केवी पिन इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5077) (UBN- VVN2526GLOB00985), 45 के एन टी एचडी सी टाइप टाइप ड्रिक इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5078) (UBN- VVN2526GLOB00986), 11 केवी हॉर्न गैंग फ्यूज सेट पोस्ट इन्सुलेटर के साथ (निविदा संख्या-5079) (UBN- VVN2526GLOB00987), 33 केवी एवं 11 केवी आईसोलेटर के फिक्स्ड कॉन्टेक्टर (जी) एवं मूविंग कॉन्टेक्टर (पाइप) (निविदा संख्या-5080) (UBN- VVN2526GLOB00988) की खरीद हेतु ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के बोरे में अन्य विवरण वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं <http://energy.raajasthan.gov.in/jvnl> द्वारा जाने जा सकते हैं। भविष्य में निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन / तिथि बदले की जानकारी केवल वेबसाइट www.eproc.raajasthan.gov.in एवं <http://energy.raajasthan.gov.in/jvnl> पर उपलब्ध कराई जाएगी। जेबीआर-3121 (2026) राज.सं.वाद /सी / 25 / 19727

अधीक्षण अभियन्ता (एम. एम. प्रथम)
बिजली विभागों के लिए टेंडर की नम्बर 1800 180 8507

राजस्थान आवासन मण्डल

हमारा प्रयास, सबको आवास

ई-ऑक्शन के माध्यम से

व्यावसायिक / आवासीय प्रीमियम संपत्तियों को खरीदने का सुनहरा अवसर

ई-ऑक्शन 25 से 27 फरवरी, 2026

बड़े व्यावसायिक भूखण्ड	स्वतंत्र निर्मित आवास एवं फ्लैट
जयपुर - 10	अलवर - 01
भिवाड़ी - 18	भरतपुर - 01

आवा

राज्य बजट 2026-27 में किसान कल्याण पर विशेष फोकस

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में किसान कल्याण पर विशेष फोकस रखा है। बजट वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड एक लाख 19 हजार 408 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 7.59 प्रतिशत अधिक है। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से किसानों की आय, उत्पादकता और कृषि अवसरंचना को नई मजबूती मिलेगी तथा राजस्थान को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

590 करोड़ रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे करीब 26 हजार किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।सिंचाई और खेतों की आधारभूत सुविधाओं के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्रस्तावित है। इसके तहत 8 हजार डिगियाँ, 15 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन तथा अगले दो वर्षों में 36 हजार फार्म पॉण्ड बनाए जाएंगे, जिससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

■ रबी दलहनों का उत्पादन 22.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 26.61 लाख मैट्रिक टन अनुमानित

■ मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में लक्ष्य के मुकाबले 99 प्रतिशत से अधिक गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित

50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम कृषक संख्या 10 से घटकर 7 कर दी गई है। इसके अलावा 50 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान तथा 500 कस्टम हार्यरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में उन्नत बीजों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख किसानों को मूंग, 1-1 लाख किसानों को मोठ और ज्वार-बाजरा-बरसीम के मिनीकित वितरित किए जाएंगे। 2.50 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच हजार से अधिक आबादी वाली 3496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। प्रथम चरण में 2098 ग्राम पंचायतों में लगभग 270 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत 'राज कृषि सूचना एवं प्रबंधन प्रणाली' विकसित की जाएगी। एआई, एमएल, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य निगरानी और जोखिम प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 'मिशन राज गिफ्ट' भी

प्रारंभ किया जाएगा।

राजस्थान कॉर्पोरेट डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया है। 'सरस' ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए एनसीआर, यूपी और एमपी में आउटलेट्स खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 1.12 लाख किंवदंतल बीज वितरित किए गए। नई किस्मों के 31.50 लाख बीज मिनीकित निःशुल्क दिए गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6,206 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवार लाभान्वित हुए। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन खरीदने पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया गया।

विधायक रोहित बोहरा ने किया

अभद्र इशारा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा अभद्र इशारा करते हुए कैमरे में कैद हो गए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों के लोकार्पण शिलान्यास का मुद्दा उठा रहे थे। रोहित बोहरा उनके पीछे बैठे थे।

इस दौरान बोहरा ने किसी विधायक को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, थोड़ी ही देर में उन्होंने हंसेंते हुए हार्म से अभद्र इशारा किया था। यह सब विधानसभा की लाइव फीड के कैमरों में भी कैद हो गया था। हालांकि विधानसभा सदन में अब तक किसी विधायक ने इस पर चर्चा नहीं की थी। देर शाम सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।



भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर “बजट राजस्थान 2026-27” के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। कटारा ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दौसा तहसीलदार की कार्यशैली पर विधानसभा में हंगामा

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को दौसा तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने शून्यकाल के दौरान तहसीलदार पर मनमाणी और एससी वर्ग के लोगों के मकान तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार बचिव तबके के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और उनका व्यवहार भी अत्यंत खराब है। बैरवा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल अपमानजनक है, बल्कि पूरे सदन के

■ कांग्रेस विधायक बैरवा वेल में पहुँचे तो स्पीकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया

लिए चिंताजनक है। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

मामले को लेकर सदन में माहौल उस समय गरमा गया जब विधायक बैरवा वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए इसे अनुशासनहीनता करार दिया। उन्होंने बैरवा को मर्यादा में रहने की हिदायत दी

17 फरवरी को बजट बहस का जवाब देंगी सरकार

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर कार्य सलाहकार समिति (बीएसी) ने 19 फरवरी तक का विस्तृत कामकाज तय कर दिया है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सदन में बीएसी का प्रतिवेदन पेश करते हुए आगामी दिनों की कार्यवाही की रूपरेखा साझा की। बीएसी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12, 13, 16 और 17 फरवरी को राज्य बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। इन चार दिनों के दौरान पक्ष और विपक्ष के विधायक बजट के विभिन्न प्रावधानों, घोषणाओं और वित्तीय प्रबंधन पर अपनी बात रखेंगे।

बजट को लेकर पहले ही सदन में तीखी बहस के संकेत मिल चुके हैं और आने वाले दिनों में यह चर्चा और तेज होने की संभावना है। आगामी 14 और 15 फरवरी को विधानसभा की कार्यवाही अवकाश के कारण स्थगित रहेगी। इसके बाद 17 फरवरी को डिप्टी सीएम एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी बजट पर हुई चर्चा का जवाब देंगी। माना जा रहा है कि वे विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों- कर्ज, घोषणाओं के क्रियाव्यवस्था, सामाजिक योजनाओं और किसानों से जुड़े विषयों-पर सरकार का पक्ष विस्तार से रखेंगी।

विधानसभा में फिर गुंजा खेजड़ी संरक्षण का मुद्दा

विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े प्रकरण भी उठाए

जयपुर (विसं)। राज्य विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान स्थान प्रस्ताव के जरिए विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने खेजड़ी के संरक्षण का मामला प्रमुखता से उठाते हुए इसे प्रदेश की लाइफ लाइन बताया। वहीं अन्य विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

हरीश चौधरी ने कहा कि खेजड़ी का अस्तित्व संकट में है और बीकानेर

सहित कई क्षेत्रों में इसके संरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। हम सब इस मामले में विफल रहे हैं, लेकिन अब मिलकर इसे रोकना होगा, उन्होंने कहा। चौधरी ने बताया कि टेनेसी एक्ट लागू होने के समय खेजड़ी एक प्रकार की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन आज यह प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है।

चौधरी ने चर्चा के दौरान एक समाज विशेष का उल्लेख किया, जिस

पर विधायक पटेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि उनका नाम लिया जा रहा है तो उन्हें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

इस बात को लेकर दोनों विधायकों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करने के निर्देश दिए। टोका-टाकी के बीच चौधरी ने कहा कि आवश्यकता होगी तो वे नोटिस देंगे। भी बात करेंगे, लेकिन खेजड़ी का संरक्षण अत्यंत जरूरी है।

6 करोड़ रुपए के गांजा तस्करी करने वाले को राहत नहीं

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंकाक से करीब छह करोड़ रुपए के हाईड्रोपोनिक वीड (गांजा) की तस्करी के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश इज्जतित कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने साधारण गांजा नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और कई गुणा नशीला हाईड्रोपोनिक वीड की तस्करी की है। ऐसे मादक पदार्थ युवाओं को नशे का आदि बना रहे हैं।

फैक्ट्री से 1000 किलो साँस सीज

जयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान खाद्य सुरक्षा एवं और स्वास्थ्य टीम टीम ने गुरुवार को मुहाना मंडी स्थित मैसर्स श्री श्याम फूड इंडस्ट्री पर कार्यवाही कर मिलावट के संदेह पर एक हजार किलो साँस सीज किया। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस फैक्ट्री से उत्पादित श्री श्याम ब्रांड साँस का नमूना जांच रिपोर्ट में अनसफ पाया गया था। जिस पर टीम और रिसर्चलिंग के निर्देश पर टीम इस फैक्ट्री पर पहुँची। मौके पर टीम द्वारा स्नैक्स साँस और रेड चिली साँस के नमूने लेकर शेष एक हजार किलो साँस में कलर मिला होने एवं अन्य कोई मिलावट होने का संदेह होने पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सीज किया गया। मौके पर फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, साँस, आचार आदि लगभग 150 किलो एम्पयर पाए गए। जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया।

‘नेता प्रतिपक्ष को फॉर्च्यूनर मिलने से हुई डोटासरा को तकलीफ’

भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने सदन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर कटाक्ष किया

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान भाजपा विधायक कैलाश वर्मा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्रियों के लिए वाहन हर सरकार में खरीदे जाते हैं, इसमें मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर ली गई तो डोटासरा को तकलीफ हो गई। यही फॉर्च्यूनर

मंत्रियों के साथ नेता प्रतिपक्ष को भी मिली है। मुझे लगता है उन्हें इस बात से ज्यादा परेशानी है कि नेता प्रतिपक्ष को यह सुविधा कैसे मिल गई।

इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। हंगामे के बीच कैलाश वर्मा ने आपत्ति करने वाले विधायकों से कहा, मुझे क्या बोलना है, यह आप तय नहीं करेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। विपक्ष

के विरोध के कारण सदन में कुछ देर तक शोर-शराबा रहा, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

बजट पर चर्चा के दौरान कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को विरासत में कर्ज का बड़ा बोझ देकर गई है और वित्तीय स्थिति को बिगाड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर किया।

भजनलाल सरकार का तीसरा बजट “विकसित राजस्थान” का रोडमैप : डॉ. प्रेमचंद बैरवा



उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की।

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को विकसित राजस्थान का रोडमैप बताया। बीजेपी ऑफिस में प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा प्रस्तुत 6.10 लाख करोड़ रुपये का बजट, वर्ष

2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। अवसरंचना विकास के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ (53 प्रतिशत वृद्धि), शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ (35 प्रतिशत वृद्धि), कृषि बजट में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान

किया गया है। 400 विद्यालयों को सीएम राज्ज विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भी कैंडलैड जारी किया गया है।

किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण और 800

करोड़ ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेखावाटी तक यमुना जल लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी। जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के अनुरूप 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आधार स्तंभ साबित होगा।

डीजीपी राजीव शर्मा ने ली पुलिस और पर्यटन विभाग की बैठक



पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने गुरुवार को पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की।

जयपुर। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामों के लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पुलिस व पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। डीजीपी ने प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्यटन स्थलों पर स्थापित पर्यटक सहायता बल (टीएएफ) को और सुदृढ़ करने, पर्यटन थांनों की संख्या बढ़ाने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित पुलिस बल लगाने और इन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हाल ही में पर्यटन विकास के लिए बजट में दी गई स्वीकृति पर कार्ययोजना तैयार करने व पर्यटन स्थलों पर विशेष त्योहारों, मेलों के साथ-साथ सामयिक आयोजनों में भी पर्यटन विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य भर के विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों तथा खादू श्यामजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, रामदेवरा, गोमामेड़ी, पुष्करजी, श्रीनाथद्वारा, सांवरियाजी आदि में कुशल प्रबंधन के लिए देवस्थान, पुलिस व प्रशासन मिलकर कार्य करें और पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाएं करें। बैठक में डीजी (ट्रेफिक) अनिल पालीवाल ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए की

जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न दूतावासों से संपर्क कर पर्यटन आमंत्रण की बात कही। आईजी अजयपाल लांबा ने डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों को नियोजित करने, एक ही स्थान पर समस्त सरकारी कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पर्यटन स्थलों पर अधिकाधिक सीसीटीवी कवरेज करने, पांच डेस्टिनेशन जहां सबसे ज्यादा टयूरिस्ट आते हैं वहां पर्यटन थांना बनाने, टयूरिज्म के नेशनल पोर्टल पर राज्यों के पोर्टल को लिंक करने आदि के सुझावों की जानकारी दी। बैठक में पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड ने पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति और वहां पर विभाग द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री, बुध डिजाइन, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी दी।

खादूश्यामजी मेले में विशेष प्रबंध करें

डीजीपी शर्मा ने खादूश्यामजी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्यटन पुलिस और टीएएफ की ओर से विशेष प्रबंध किए जावें।

उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह-जगह पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कक्ष नंबर, पुलिस हेल्पलाइन 112, राजकाप सिटीजन एप आदि के लिंक इत्यादि दर्शाती हुई स्टैंडीज व टीएएफ की ओर से विशेष सहायता वृथ स्थापित करने के निर्देश दिए और कहा कि टीएएफ की उपस्थिति दिखनी चाहिए।

पर्यटकों को मिले बेहतर सुविधाएं : डीजीपी ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अमेर की केस स्टडी में आई अपेक्षाओं को समस्त पर्यटक स्थलों पर लागू करने की बात कही। उन्होंने सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के साथ-साथ पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण और आवागमन के लिए व्यवस्थित सड़क सुविधा के साथ-साथ पर्यटकों के लिए अपेक्षित सुचनाओं की उपलब्धता के संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के साथ-साथ रेल्वे स्टेशन, हवाई अड्डा और अन्य स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक सहायता वृथ स्थापित हो जहां पर पर्यटक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संपर्क कर सकें। बैठक में एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) वी.के.सिंह, एडीजी (ट्रेफिक) बीएल मीणा सहित पर्यटन, आरटीडीसी,आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम और संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

कोटा में अवैध हथियार व वाहन सहित हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

आरोपी के पास से 2 देशी पिस्टल, 5 देशी कट्टे व 27 जिंदा कारतूस बरामद किये

कोटा, (निंस्)। रानपुर पुलिस टीम ने इलाके में आकस्मिक चैकिंग के दौरान अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाने के हिस्ट्रीशीटर कालू भड़क को सात अवैध हथियारों व 27 जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने पकड़े गये आरोपी के पास से 2 देशी पिस्टल मय मैगजीन मय 4 अतिरिक्त मैगजीन, 5 देशी कट्टे व 27 जिंदा कारतूस बरामद किये है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान कुछ हथियार मौके पर उसके वाहन से जब्त किये हैं एवं कुछ हथियार व कारतूस पकड़े गये आरोपी के घर से बरामद किये है।



शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जानकारी दी।

शहर पुलिस अधीक्षक तेजस्वनी गौतम ने बताया कि अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई के लिये शहर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी के निर्देशन में विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। शहर एसपी तेजस्वनी गौतम ने बताया कि रानपुर थाने के उप निरीक्षक थानाधिकारी भीमसिंह मय जाब्ता इलाके में गश्त

कर रहे थे, गश्त के दौरान थानाधिकारी ने सूचना के आधार पर रानपुर के रीको क्षेत्र में मय जाब्ता मौके पर पहुंचकर टाटा सफारी गाड़ी को रोक कर उसकी तलाशी ली तो, तलाशी के दौरान

में कार्रवाई करते हुए लखावा निवासी कालू भड़क उर्फ कालू (45) को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियारों सहित पकड़ा गया आरोपी कालू भड़क थाने का हिस्ट्रीशीटर भी है, पकड़े गये आरोपी से अनुसंधान के बाद पुलिस टीम ने आरोपी के घर से भी 4 देशी कट्टा 12 जिंदा कारतूस व 2 मैगजीन बरामद किये।

शहर एसपी ने बताया कि पकड़े गये आरोपी से हथियारों की खरीद-फरोख्त एवं मामले में अन्य आरोपियों की संलिप्ता के बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। शहर एसपी ने बताया कि उक्त कार्रवाई पुलिस उप अधीक्षक मनीष शर्मा के सुपरविजन में की गई।

मादक पदार्थ सहित तीन गिरफ्तार

टोंक, (निंस्)। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम प्रभारी ओमप्रकाश नेतृत्व में गठित टीम द्वारा जिले के तीन थाना क्षेत्रों में छापामारी नशे के खिलाफ कार्रवाई कर अवैध मादक पदार्थ सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

इस कार्रवाई के दौरान टोंक सदर थाना क्षेत्र स्थित बंबोर रोड पर अम्बेडकर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड निवासी सनी सांसी के कब्जे से एक मोटरसाइकिल पर करीब 50 हजार रुपये कीमत का एक किलोग्राम से अधिक अवैध मादक पदार्थ गांजा व 1०0 लीटर हथकड़ शराब जब्त की जाकर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस व एक्साइट्न एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है।

इसी प्रकार टीम ने थाना कोतवाली क्षेत्र में 99 शॉप पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी नयेद खान के कब्जे से करीबन 70 हजार रुपए कीमत की प्रतिबंधित 31 पेलवर युक्त ई सिगरेट (इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट) पांच धारदार चाकु व खरीद फरोख्त राशि 33०0 रुपये बरामद किए जाकर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया। वहीं डीएसटी टीम ने पुलिस थाना पचेवर क्षेत्र के कचोल्या ग्राम में आरोपी रामपाल जाट के कब्जे से करीबन 15 हजार रुपये कीमत का एक किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-पोस्ट बरामद किया जाकर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

डूंगरपुर में कार से 22 कार्टून अवैध शराब जब्त

शराब को डिगगी और सीटों के बीच छिपाकर गुजरात ले जा रहा ड्राइवर गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निंस्)। जिले के धंभोला थाना पुलिस ने दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह शराब कार की डिगगी और पीछे की सीटों के बीच छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

- धंभोला थाना पुलिस ने दिल्ली नंबर की एक स्विफ्ट डिजायर कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की**

संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिसके बाद पुलिस ने कार की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार की डिगगी और पीछे की सीट के बीच 22 कार्टून विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब मिली।

शराब के परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज ड्राइवर के पास नहीं थे। पुलिस ने तत्काल कार को जब्त कर लिया। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ड्राइवर धर्माराम जाट को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह शराब तस्करी कर गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है।

चोरी का सोना गिरवी रखकर लोन लिया

उदयपुर, (कांस्)। चाचा के घर से सोना चोरी कर बैंक में गिरवी रख कर ऋण लेने वाले के खिलाफ हाथीपोल थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया।

जानकारी के अनुसार पीड़ित अंकुर पुत्र पारसमल निवासी आर्वी गेलेक्सी जेन जेवली हॉल टोटिटरी मैनेजर कोटक महिन्दा बैंक लि. मधुवन बैंक स्ट्रीट ने आरोपी युवराजसिंह पुत्र दुर्जनसिंह राठौड़ निवासी साबला द्वारपुर हॉल द्राका अपार्टमेंट के पास जागर कोटड़ा रोड़ के खिलाफ प्रकरण दर्ज कवाया।

उसने बताया कि आरोपी ने आरोपी ने बैंक में चोरी किया सोना गिरवी रख कर 8 लाख रुपये का ऋण लेने का प्रकरण दर्ज करवाया। आरोपी युवराजसिंह ने 27 जनवरी 2०25 में अपने चाचा के घर से सोने के जेवरत चोरी किए थे।

घायल की मौत के बाद दूसरे दिन भी सर्व समाज में आक्रोश

भीलवाड़ा, (निंस्)। मांडल तहसील के चतरपुरा भादू गांव में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले और आगजनी के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। उदयपुर में उपचार के दौरान घायल जगदीश सिंह की मौत के बाद गुववार को लगातार दूसरे दिन भी महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी के बाहर सर्व समाज और रावणा राजपूत समाज का भारी जमावड़ा लगा हुआ है।

जानकारी के अनुसार बीती एक तारीख की रात को चतरपुरा भादू गांव में करीब 5०-60 असामाजिक तत्वों ने एक रावणा राजपूत परिवार के घर में घुसकर महिलाओं और पुरुषों पर सरियों व कुल्हाड़ियों से हमला कर दिया था। हमलावरों ने घर में आग भी लगा दी थी। इस हमले में जगदीश सिंह गंभीर रूप से

- प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए**

- सर्व समाज का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है**

घायल हो गए थे, जिन्होंने बुधवार रात दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द की जाए, परिवार ने 25-3० लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी

थी, लेकिन पुलिस ने अब तक केवल 1-2 लोगों को ही पकड़ा है।

सर्व समाज का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। जब तक सभी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यह केवल एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि मानवता पर हमला है। जब तक जगदीश सिंह के हत्यारे सलाखों के पीछे नहीं होंगे, समाज पीछे नहीं हटेगा। अस्पताल परिसर में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारी समाज के प्रतिनिधियों के साथ वार्ता कर मामला शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रदर्शनकारी सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं।

अवैध अफीम व गांजा सहित दो गिरफ्तार

उदयपुर, (कांस्)। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने तलाशी अभियान के दौरान अवैध अफीम मय कार जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अन्यत्र माण्डवा थाना पुलिस ने बाइक सहित अवैध गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया।

जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल, पुलिस उप अधीक्षक राजीव राहट के सुपरविजन में खेरवाड़ा थानाधिकारी करनाराम के नेतृत्व में गठित दल ने 11 फरवरी रात में गश्त के दौरान खावड़ी ओवरी टोल से आगे राजस्थानी ढाबा के बाहर एक कार को देख चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ की तो उसने अपना नाम

नन्दलाल पुत्र रसीकलाल निवासी खापंडी ओवरी उपला फला खेरवाड़ा होना व पास सीट पर रखी थेली में पीसा हुआ अवैध 846 ग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा होना बताया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर एक मय अफीम डोडा-चूरा जब्त कर प्रकरण दर्ज किया।

इसी तरह माण्डवा थानाधिकारी निर्मल कुमार मय टीम ने नाकाबंदी के दौरान बिकरनी मरोड़ पर बाइक को रोक तलाशी ली तो चालक पंकज राव पुत्र मदनलाल निवासी गोगुन्दा फला महादेव जी की बावड़ी के पास रखे कट्टे की तलाशी ली तो उसमें 7.810 किलोग्राम अवैध गांजा पाया गया। इस पर मादक पदार्थ मय बाइक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया।

भीलवाड़ा में हवाला के 24 लाख रुपये के साथ दो को पकड़ा

- पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश और गुजरात के रहने वाले हैं, जो कजुकांति नामक हवाला नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे**

महावीर सुगंध वाली गली में दो युवक बैग लेकर जा रहे हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में कैश होने की संभावना है। सूचना मिलते ही कोतवाली थानाधिकारी शिवराज गुर्जर के नेतृत्व में एएसआई सुरेश कुमार और टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देख युवक घबरा गए। संदेह होने पर जब उनके बैग की तलाशी ली गई, तो उसमें 500 और 2०0 रुपये के नोटों की थड्डियां बरामद हुईं। पुलिस ने जब

बरामद राशि के संबंध में दस्तावेज या लाइसेंस मांगे, तो आरोपी कोई भी वैध रसीद पेश नहीं कर सके। इस पर पुलिस ने राशि जब्त कर दोनों आरोपी गोपाल सिंह पुत्र मानसिंह परमार निवासी उज्जैन (म.प्र.) और सिद्धराज सिंह पुत्र भंवर सिंह वाघेला निवासी मेहसाना (गुजरात) को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके।

बंद पेंशन वापस चालू कराने के नाम पर ठगी

बयाना/भरतपुर, (निंस्)। बयाना कस्बे में सायबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। रेलवे विभाग के नाम पर झंसा देकर एक व्यक्ति के खाते से 63 हजार रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है और पुलिस जांच में जुटी हुई है।

मामला बयाना कस्बे की सुनार गली का है, जहां निवासी जयप्रकाश सोनी सायबर ठगी का शिकार हो गए।

गांजा और स्मैक बेचते एक व्यक्ति गिरफ्तार

भरतपुर, (निंस्)। भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसके कब्जे से अवैध गांजा और स्मैक बरामद की गई है। पुलिस को देखकर एक व्यक्ति फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दोनों व्यक्ति लोगों को स्मैक और गांजा बेचते थे, जिन्हें पुडिया में बांधकर रखा हुआ था। वहीं मामले को लेकर मथुरा गेट थाना पुलिस जांच कर रही है।

मथुरा गेट थाना अधिकारी देरावर सिंह भाटी ने बताया कि एक टीम अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए रवाना हुई। रात में पुलिस की टीम श्याम नगर तिराहे पर पहुंची। जहां मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि दो व्यक्ति केंद्रीय विद्यालय के पीछे एक निकालकर इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो, एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा।

एक व्यक्ति दुकान के अंदर कुर्सी पर बैठे था, जिसे पुलिस की टीम ने पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम अमित निवासी श्याम नगर हवा बताया। अमित के पास दो थैली रखी हुई थी, जिसमें से एक थैली को खोलकर

- पुलिस को देख एक व्यक्ति फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है**

- दोनों व्यक्ति लोगों को स्मैक और गांजा बेचते थे, जिन्हें पुडिया में बांधकर रखा हुआ था**

देखा तो, उसके अंदर सफेद कागज की दो छोटी-छोटी 28 पुडिया रखी थी। उसमें से एक पुडिया को खोलकर देखा तो, उसमें स्मैक थी। सभी पुडिया से स्मैक निकालकर इकट्ठा किया। तोलने पर 2.97 ग्राम स्मैक पाई गई। दूसरी थैली को देखा तो उसमें 6 पुडिया थी। जिनमें गांजा भरा हुआ था।

वजन कर पर 3.80 ग्राम गांजा पाया गया। अमित ने बताया कि जो व्यक्ति भागा था जितेंद्र वह गांजा और स्मैक बेचता है। पुलिस ने अमित को गिरफ्तार कर लिया और जितेंद्र की तलाश की जा रही है।

लैपर्ड ने चार बकरियों को मारा

टोंक, (निंस्)। निवाड़ उपखंड के छोटी बरथल गांव में लैपर्ड ने एक बार फिर पशुओं पर हमला कर चार बकरियों को मार डाला। यह 20 दिनों में चौथी घटना है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।

जानकारी के अनुसार गुरुवार रात गांव बरथल के भैरूजी के मंदिर के पास स्थित गजानंद बेफलावत के बाड़े में हुई हलचल से ग्रामीणों की नींद खुल गई, शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिसके बाद लैपर्ड अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गया। पीड़ित गजानंद बेफलावत के लिए बकरियां आय का मुख्य स्रोत थी। घटना की सूचना निवाड़ वन विभाग को दी गई, जिसके बाद रंजर धारीलाल बैरवा ने अपनी टीम के साथ मौके का मुआयना किया। ग्रामीणों के बड़ते रोष को देखते हुए विभाग ने जानवर को पकड़ने के लिए क्षेत्र में दो पिंपरे लगाए हैं। फॉरेस्ट रेंजर बैरवा ने बताया कि वन विभाग की टीम निगरानी कर रही है और जल्द ही लैपर्ड को पकड़ लिया जाएगा।

भीलवाड़ा में दूसरे दिन भी अवैध कब्जे हटाये

भीलवाड़ा, (निंस्)। शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में नगर निगम का अभियान गुरुवार को और भी आक्रामक रूप में दिखाई दिया। निगम के दस्ते ने शहर के व्यस्ततम हरीसेवा मार्ग और प्रताप टॉकीज के आस-पास के इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान वर्षों से जमे पक्के अतिक्रमणों को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरे व्यापारिक क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

जानकारी के अनुसार, हरीसेवा मार्ग पर कई व्यापारियों ने अपनी दुकानों के बाहर स्थायी चबूतरे और अस्थायी टिनशेड लगाकर सार्वजनिक मार्ग को काफी संकरा कर दिया था। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही थी। बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद

निगम प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। गुरुवार दोपहर जैसे ही जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंचीं, दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

टीम ने एक-एक कर अवैध रूप से बने चबूतरों को तोड़ दिया और अवैध केबिनों को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानों पर व्यापारियों ने विरोध दर्ज कराया और कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। हालांकि, मौके पर तैनात पुलिस बल और निगम अधिकारियों ने दो-दुक शब्दों में कह दिया कि सार्वजनिक जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही और शाम तक मार्ग को काफी संकरा कर दिया था। इससे वाहन चालकों और पैदल चलने वाले राहगीरों को भारी परेशानी हो रही थी। बार-बार मिल रही शिकायतों के बाद

पत्थरों से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त बिना रक्ता (परिवहन दस्तावेज) के चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाकर कार्रवाई की

भरतपुर, (निंस्)। भरतपुर में अवैध खनन के खिलाफ पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह की सूचना पर पुलिस ने चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की। विश्वेंद्र सिंह ने अलसुबह करीब 3:3० बजे पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली निकलने की सूचना पुलिस को दी थी, लेकिन करीब 2० मिनट इंतजार के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इसके बाद सुबह करीब आठ बजे उन्होंने सेवक थाने के सामने दोबारा ऐसे वाहन देखे। पुलिसकर्मी को थाने से बुलाकर लाने पर चार ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त करने की कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भुववार सुबह मोती महल से सुप्रभातम की

पूजा-अर्चना कर जवाहर फार्म लौट रहे थे। इसी दौरान सफ़ेद हाउस चौराहे के पास उन्हें अवैध खनन सामग्री (पत्थरों) से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली नजर आई। इसकी सूचना सीओ सिटी को दी। सीओ ने मथुरा गेट थाने को सूचना देने की बात कही। विश्वेंद्र सिंह के अनुसार, सूचना देने के बाद वे करीब 2० मिनट तक मौके पर इंतजार करते रहे, लेकिन न तो पुलिस पहुंची और न ही कोई जवाब मिला। उन्होंने दो बार कंट्रोल रूम पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। उन्होंने अपनी पोस्ट में इसे पुलिस प्रशासन की लापरवाही बताते हुए कहा कि इसी कारण शहर में अवैध खनन से भरे वाहनों का आवागमन भड़कले से हो रहा है। विश्वेंद्र सिंह ने आगे बताया कि

सुबह करीब 8 बजे जब वे सेवर थाने के सामने से गुजर रहे थे, तो वहां भी अवैध खनन से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जड़ी मिली। उन्होंने अपने पीएसओ को थाने के अंदर भेजकर पुलिसकर्मी को बुलाया। करीब 1० मिनट बाद सेवर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद बिना रक्ता (परिवहन दस्तावेज) के चल रहे ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाया गया।

सेवर थाना एचएसओ सतीश भारद्वाज ने बताया कि शिकायत के आधार पर पत्थरों से भरी चार ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि खनन सामग्री कहाँ से लाई गई और संबंधित दस्तावेज वैध थे या नहीं।

‘‘राइट टू हैल्थ’’ एक्ट पर विधानसभा में सत्ता पक्ष व विपक्ष में घमासान

सरकार का कहना था कि मौजूदा योजनाओं में स्वास्थ्य का अधिकार मिल रहा है, अलग कानून की जरूरत नहीं

जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान विधानसभा में गुरूवार को प्रश्नकाल के दौरान स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम-2०22 (राइट टू हेल्थ) को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार हंगामा देखने को मिला। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया।

विधायक हरिमोहन शर्मा ने, अप्रैल 2०23 में अधिसूचित राइट टू हेल्थ एक्ट के नियम अब तक लागू नहीं किए जाने पर सरकार से जवाब मांगा। उन्होंने पूछा कि नियम क्यों नहीं बनाए गए, प्राप्त सुझावों पर क्या निर्णय हुआ और इस संबंध में हुई बैठकों का ब्यौरा क्या है? साथ ही, उन्होंने हाईकोर्ट के नोटिस

- कांग्रेस का कहना था कि नियम नहीं बना कर जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉक आउट किया।

और सरकार के जवाब की जानकारी भी मांगी।

इस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खीवरसर ने कहा कि पिछली सरकार चुनाव से ठीक पहले बिना पर्याप्त तैयारी के यह अधिनियम लेकर आई थी। नियम नहीं बनाए गए और हितधारकों से समुचित चर्चा भी नहीं की गई। उन्होंने बताया कि अधिनियम के नियमों को लेकर हाईकोर्ट में पीआईएल लंबित है और निर्णय प्रतीक्षित है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही “मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (मा) योजना” के तहत 25 लाख रुपये तक का वार्षिक कैंशैलस इलाज उपलब्ध करा रही है। योजना के तहत 1.36 करोड़ पात्र परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है और 217.9 उपचार पैकेज इसमें शामिल हैं। निःशुल्क जांच, दवाइयां, ओपीडी, आर्थोपीडी, आपातकालीन सेवाएं, हीमोडायलिसिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं पहले से दी जा रही है।

ऐसे में अलग से इस एक्ट की आवश्यकता नहीं है।

मंत्री के बयान पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष ने सीधा सवाल किया कि सरकार राइट टू हेल्थ लागू करना चाहती है या नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि नियम नहीं बनाकर जनता के स्वास्थ्य अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत दी और चेतावनी दी कि स्थिति नहीं संभली तो सदन स्थगित करना पड़ेगा। अंततः विपक्ष ने विरोधस्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बता दिया है कि फिल्म का नाम बदला जा रहा है और टेलर तथा प्रचार सामग्री पहले ही वापस ले ली गई है।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं से यह भी बताने को कहा कि क्या फिल्म “बूसखोर पंडित” में किसी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक सामग्री दिखाई गई है।

कोर्ट ने फिल्म निर्माताओं से इस संबंध में हलफनामा भी मांगा है।

अदालत ने, “फ्राईडे फिल्मवक्स” द्वारा निर्मित इस फिल्म की टीम को फटकार लगाते हुए पूछा कि फिल्म निर्माता संयम क्यों नहीं बरत सकते।

बेअसर रहा भारत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
की सभी ट्रेड यूनियनं, किसान और मजदूर मोदी सरकार के व्यापार समझौते, श्रम कानूनों और मनरेगा को समाप्त करने के खिलाफ सड़कों पर हैं। ओडिशा, केरल, तमिलनाडु, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और पंजाब सहित, कई राज्यों में मिला-जुला असर देखने को मिला।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने मजदूरों और किसानों के भविष्य से जुड़े निर्णय लेते समय उनकी

कोर्ट ने कहा, “जब समाज में पहले से ही विभाजन है, तो किसी समाज के एक वर्ग को बदनाम क्यों किया जाना चाहिए?”

‘वोकिज्म’ को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे फिल्म शोर्षक समाज में अशांति पैदा करते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भाईचारा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसे सीमित नहीं कर सकती।

“बूसखोर पंडित” विवाद में तब आई, जब 3 फरवरी को नेटफ्लिक्स इंडिया के 2०26 लॉन्च कार्यक्रम में इसका शीर्षक और टीजर सामने आया।

आवाजों को नज़रअंदाज़ किया।
केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच से जुड़े कर्मचारियों और मजदूरों ने आज दिनभर की हड़ताल कर केन्द्र सरकार की मजदूर-विरोधी, किसान-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी कार्रगोरेट समर्थक नीतियों के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। मंच ने दावा किया कि नई श्रम संहिताओं सहित, अन्य मुद्दों के विरोध में सामान्य हड़ताल के लिए 30 करोड़ मजदूरों को संगठित किया जा रहा है।

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के स्थान के बाद केन्द्र सरकार से मंजूरी पाने वाली पहली बड़ी नई परियोजना है। इसके अलावा, पाकल डुल, किरू और रतले बांध परियोजनाओं की भी शुरु करने की प्रक्रिया चल रही है। भारत सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से पानी के प्रवाह का बेहतर प्रबंधन होगा और देश की बिजली उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी।

पाकिस्तान भारत की इन कार्रवाइयों का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भारत द्वारा बांध बनाने से

कायदे, कानून व प्रक्रिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इसे फर्जी ही कहा जा सकता है।

लेकिन सरकार की हर बात को दोहराने वाला सुविधाजनक गोदी मीडिया यह खबर चला रहा है कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाएगा।

यह बात निश्चित रूप से हर उस भाजपा समर्थक के दिल और दिमाग में

पाकिस्तान को मिलने वाले सिंधु नदी के साझा पानी के प्रवाह पर गंभीर असर सकता है, जिससे उसके देश के अस्तित्व से जुड़ा जल अधिकार प्रभावित होगा।

भारत द्वारा चिनाब नदी पर 5129 करोड़ रुपये की सावलकोट जलविद्युत परियोजना पर काम शुरू करने की खबरों के बाद पाकिस्तान सरकार ने सिंधु बॉर्डर्स कमिशनर के स्तर पर चिंता जताई है और इस परियोजना से जुड़ी जानकारी और बातचीत की मांग की है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा, “सिंधु

जल संधि एक “बाईडिंग इन्टरनैशनल इन्स्ट्र्यूमेंट” (बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता) है और कोई भी एकतरफा कदम या अवहेलना इस कानूनी स्थिति को नहीं बदल सकती। अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान भारत की कार्रवाइयों को चुनौती देगा, क्योंकि देश के लगभग तीन चौथाई पानी का स्रोत चिनाब जैसी पश्चिमी नदियां हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान भारत के साथ विवादों और मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान बातचीत और अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था के जरिए करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

- “डिस्क्वालिफिकेशन” करने के लिए कायदे-कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी कान होना, फिर कार्रवा बना, राहुल गांधी को “डिस्क्वालिफाई” करने के प्रयास के असफल होने का।

हो सकता है जो राहुल गांधी से नफरत करता है, और ऐसे लोग काफी संख्या में हैं। लेकिन बिना सही नियम और

प्रक्रिया के यह सपना हकीकत कैसे बनेगा? यही वह मुख्य सवाल है, जिसे पूछा जाना चाहिए।

करने की कोशिश की जाती है। डिजिटल युग में, अभिलेखों से हटाए गए अंश अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड से बाहर व्यापक रूप से प्रसारित हो जाते हैं, जिससे संसंरक्षित या व्यवहारिक प्रभाव सीमित हो जाता है और राजनीतिक बहस और तेज हो जाती है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय जांचों से जुड़े संभावित भविष्य के खुलासों से सम्बन्धित अटकलों ने राजनीतिक माहौल में अनिश्चितता का तत्व जोड़ दिया है। यद्यपि शोर्ष भारतीय नेतृत्व को फंसाने वाले किसी संभावित खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसी रिपोर्टों का प्रसार ही राजनीतिक हलकों में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। ऐसे माहौल में संसदीय टकराव को बढ़ाना अनिश्चित परिणामों वाला दुःसाहस माना जा सकता था।

मोदी सरकार के सामने दृढ़ता और संयम के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती है। बिना किसी न्यायिक दोषसिद्धि या स्पष्ट संवैधानिक आधार के, नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता समाप्त

‘संविधान के अनुरूप है एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव’

नई दिल्ली, 12 फ़रवरी। “एक राष्ट्र, एक चुनाव” को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की गुरुवार को हुई बैठक में पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने कहा कि एक राष्ट्र, एक चुनाव का प्रस्ताव संविधान के अनुरूप है और यह मूल द िचे का उल्लंघन नहीं करता। उन्होंने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है और यह उसका विशेषाधिकार है। इसमें लोकतंत्र या संघीय द िचे का कोई उल्लंघन नहीं है।

बैठक के बाद संसद के बाहर जेपीसी के अध्यक्ष भीमजाप सांसद पीपी चौधरी ने पत्रकारों को जानकारी दी कि बैठक में सभी सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे। पूर्व न्यायमूर्ति बीआर गवई ने बैठक में आकर सदस्यों द्वारा संवैधानिक बैधता से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा सभी दलों को राष्ट्रीय हित में एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए, ताकि विषय के सामने देश की एकता प्रदर्शित हो सके। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनावी सुधारों

मोदी आज नए ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे

नई दिल्ली, 12 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 फरवरी को नए प्रधानमंत्री ऑफिस ‘सेवा तीर्थ’ में शिफ्ट होंगे। जानकारी के अनुसार, मोदी दोपहर करीब 1:30 बजे ‘सेवा तीर्थ’

- सेवा तीर्थ के साथ ही कर्तव्य भवन-1 और 2 का भी शाम 6 बजे उद्घाटन होगा।

बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के नाम का अनावरण करेंगे।फिर शाम करीब 6 बजे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन-1 और 2 का उद्घाटन करेंगे।

इसके बाद, पीएम एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। कर्तव्य भवन-1 और 2 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के नए ऑफिस होंगे। वर्तमान में पीएमओ और मंत्रालयों के ऑफिस नई दिल्ली स्थित सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में हैं।

‘दिल्ली हवा खाने नहीं आए हैं, राजनीति करने आए हैं’

कर्नाटक के नेता शिवकुमार ने दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए टिप्पणी की

- डी के शिवकुमार ने खड़गे, सोनिया, राहुल और प्रियंका से मुलाकात की।
- शिवकुमार की इस मीटिंग के बाद एक बार फिर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा शुरु हो गई है।

हालांकि शिवकुमार ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाड़ा से मुलाकात पर सीधा जवाब नहीं दिया। शिवकुमार की इस मुलाकात के बाद कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें लगाई जा रही है।

‘दूषित फल-सब्जियों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
अदालत ने पूछा कि राज्य सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि डेयरियों में पहुंचा हुआ दूध मिलावटी नहीं है। इस दौरान पूर्व महाधिवक्ता सिंघवी ने कहा कि पशुओं को ऑक्सिटीसीन इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे दूध उत्पादन

तालेड़ा के स्कूल में स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका पर हमला किया

बालिका के दादा के अनुसार, उसके चेहरे को छोड़कर पूरे शरीर पर घाव हैं

- कोटा मैंडिकल कॉलेज में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज देवेंदा ने बताया कि बालिका के शरीर पर करीब 20 घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में घाव हो गया, इसलिए श्वसन तंत्र को सुचारु रखने के लिए ट्यूब डाली गई है।

गए, जहां से बच्चों को कोटा रेफर किया गया है।

बालिका के दादा भंवरलाल सेन का कहना है कि वे लोग सीतापुरा रहते हैं। वहीं से बालिका स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में पढ़ने तालेड़ा जाती थी, जहां पर यह घटना हुई है। उन्होंने बताया कि स्ट्रीट डॉग्स ने बालिका को इतनी बुरी तरह काटा है कि उसके शरीर पर चरेरे को छोड़कर लगभग सभी जगह पर घाव हो गए हैं। उन्होंने बताया कि स्कूल में वे वैन से कई बार बच्चों को

लेने भी जाते हैं, तब बड़ी संख्या में स्ट्रीट डॉग्स स्कूल में घूमते नजर आते हैं। उन्होंने कहा, सरकार तत्काल इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान ले। मेडिकल कॉलेज कोटा में सर्जरी के एचओडी डॉ. नीरज का कहना है कि बालिका के शरीर पर करीब 2० के आसपास घाव हैं। उसके फेफड़ों तक में भी घाव हो गया है। इसीलिए ट्यूब डाली गई है, ताकि बालिका के श्वसन तंत्र को सुचारु रखा जा सके।बालिका के हाथ, पैर और छाती सहित, कई जगह पर घाव के निशान हैं।

भारत में निपाह वायरस से पहली मौत

नई दिल्ली, 12 फरवरी। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस से संक्रमित दो मरीजों में से एक मरीज की मौत हो गई है। देश में इस साल निपाह वायरस से यह पहली मौत है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि 11 नववरी 2०26 को पश्चिम बंगाल से रिपोर्ट किए गए निपाह संक्रमण के दो

संक्रमित नर्सिंग स्टाफ नॉर्थ 24 पराना जिले के बारासात के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थे। इनमें एक पुरुष नर्स और एक महिला नर्स शामिल थीं। पुरुष नर्स इलाज के दौरान ठीक हो गया, लेकिन महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई।

बांग्लादेश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
महिलाओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है, वहीं प्रमुख दलों ने भी उन्हें केवल औपचारिक या प्रतीकात्मक नामांकन दिए हैं। 2०26 के चुनाव महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में स्पष्ट और जबरदस्त गिरावट दर्शाते हैं और बांग्लादेश की राजनीति में लैंगिक समानता के भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। गुरुवार को चुनाव के दिन ढाका में भारी मतदान देखा गया, जहां जमात और बीएनपी के बीच मुकाबला चुनावी परिदृश्य को परिभाषित करता नजर आया। जनरेशन-ज़ैड आंदोलन के बाद हो रहे इस पहले चुनाव में जमात और बीएनपी समर्थकों के बीच झड़पों की भी खबरें सामने आईं।

श्रीलंका के लिए हवाई उड़ानों के किराए में भारी वृद्धि

भारत-पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलम्बो में होने वाले मुकाबले के कारण यह वृद्धि हुई है

- बड़ी संख्या में लोग कोलम्बो जा रहे हैं इस वजह से चेन्नई से कोलम्बो की हवाई टिकट, जो 7,127 रुपए की होती थी, के दाम बढ़कर 22 से 25 हजार तक पहुँच गए हैं।

किराया सामान्यतः कम रहता है। इसी वजह से चेन्नई से श्रीलंका जाने वाले यात्रियों की संख्या आमतौर पर अधिक रहती है।

सामान्य दिनों में चेन्नई-श्रीलंका के बीच हवाई किराया लगभग 7,127 रुपये होता है, लेकिन 13 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस की इकोनॉमी क्लास का किराया 22,073 रुपये से 25,2०7 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया

42,231 रुपये तक हो गया है। 14 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस का किराया 2०,7०8 रुपये से 25,2०7 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस का किराया 35,217 रुपये तक बढ़ गया है।मैच के दिन यानी, 15 तारीख को इंडिगो एयरलाइंस में किराया 18,283 रुपये से 19,464 रुपये तक और श्रीलंकन एयरलाइंस में 28,660 रुपये से 42,231 रुपये तक निर्धारित किया गया है।

हिंसा व हत्याओं के वातावरण ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी के बीच वोटों के लिए मुकाबला हुआ। मतदान प्रक्रिया बीएनपी और जमात के समर्थकों के बीच झड़पों भी हुई।

पहले, शेख हसीना के शासनकाल में बीएनपी और जमात ने चुनाव लड़ने के लिए आपस में गठजोड़ किया था। पर अब अवाामी लीग के मैदान में न होने से ये दोनों कट्टरपंथी दल अब एक-दूसरे से अलग हो गए हैं और सत्ता पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जमात एक इस्लामी झुकाव वाला बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रही है।

भारत के लिए ये दोनों दल एक तरह से “हांब्सन चैंडस” प्रस्तुत करते हैं, अर्थात दोनों ही मूल रूप से भारत-विरोधी हैं और दोनों ने देश में बचे हुए हिंदुओं को बाहर निकालने की दिशा में काम किया है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार मतदान की सफलता का दावा कर रही है और एक नई शुरुआत की आशा व्यक्त कर रही है।

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रियल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुरा फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायवा हाऊस, खजुरित शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भारा हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद नगर रोड आनंद, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूरी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रियल एरिया, फेस प्रथम, जालौर। फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 2304000, फैक्स: 07469-230600 चूरु कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरु, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908
